



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, बुधस्मतिवार, अगस्त 26, 2010/भाद्र 4, 1932

No. 245]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2010/BHADRA 4, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

**विषय :** चीन जन. गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों तथा लारियों/ट्रकों के बॉयस टायरों" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बारे में मध्यावधि समीक्षा जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

सं. 15/1/2009-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 जिसे आगे अधिनियम कहा गया है और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित और उप-शीर्ष क्रमशः 40112090, 40131020 तथा 40129049 के अंतर्गत आने वाले "बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉयर, ट्यूब एवं फ्लैप्स" (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणाम 19 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 14/9/2005-डीजीएडी के तहत अधिसूचित किए गए थे और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 24 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 88/2007-सी.शु. के तहत लगाया गया था ।

2. प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने तथा उसकी राशि को बढ़ाने एवं शुल्क के स्वरूप में संशोधन करने हेतु ऑटोमोटिव टायर मैय्पुफैक्चर्स एसो. (ए टी एम ए) से एक विधिवत् पुष्टिकृत आवेदन प्राप्त हुआ कि मौजूदा शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है । आवेदक ने लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसकी राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

3. इस बात से संतुष्ट होने के उपरान्त कि आवेदक ने समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए पर्याप्त सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम-23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर 27 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 15/1/2009-डीजीएडी के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की थी ।

ख. प्रक्रिया

4. इन कार्रवाइयों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था ।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 27 फरवरी, 2009 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को भेजीं । इस जांच से संबंधित पक्षकारों से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराया गया था:
- iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	क्विंगडाओ झोंगसी रबड़ कंपनी, चीन.जन.गण.
2.	शंघाई टायर एंड रबड़ कंपनी, चीन.जन.गण.
3.	एओलस टायर कंपनी लि., चीन.जन.गण.
4.	क्विंगडाओ मोनोलिथ ओ टी आर टायर कंपनी लि., चीन.जन.गण.
5.	योकोहामा टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कंपनी लि., थाईलैंड
6.	थाई ब्रिजस्टोन कंपनी लि., थाईलैंड
7.	ओटानी टायर कंपनी लि., थाईलैंड
8.	मिकेलिन सियाम कंपनी लि., थाईलैंड

मै. थाई ब्रिजस्टोन कंपनी लि. ने अपने पत्र में यह बताया कि वे भारत को संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं करते हैं और उनकी संशा भविष्य में भी इसका निर्यात करने की नहीं है । मै. योकोहामा टायर मैनुफैक्चरिंग (थाईलैंड) कंपनी लि. ने यह बताया कि उन्होंने वर्ष 2005 से 2009 के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया । इन दोनों कंपनियों को छोड़कर किसी अन्य निर्यातक ने उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है ।

- v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना हेतु भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र.सं	कंपनी का नाम
1.	रेडियल्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली
2.	करतार टायर हाऊस, नई दिल्ली
3.	काक्स एंड बिल्स प्रा.लि., नई दिल्ली
4.	राणा टायर्स, नई दिल्ली
5.	सनी इंटरनेशनल, मुंबई
6.	अमन इंटरनेशनल, मुंबई
7.	विकास रोड कैरियर्स लि., भरुच, गुजरात
8.	एएए इम्पैक्स, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध वस्तु के टायर डीलरों की एक एसोसिएशन होने का दावा करने वाली एक एसोसिएशन ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन ने ही वर्तमान मामले में उत्तर दिया। किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

- vi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए आयात के आंकड़े मांगे गए थे।
- vii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा, जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।
- viii. जैसा कि बताया गया है, मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन ए टी एम ए ने दायर किया था। संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में संलग्न ए टी एम ए के 6 सदस्य हैं, अर्थात् मै. अपोलो टायर्स लि., मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई), मै. एम आर एफ लि., मै. जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. गुडईयर इंडिया लि.। मै. अपोलो टायर्स लि., मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई) तथा मै. जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. ने क्षति विश्लेषण करने हेतु सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जबकि मै. एम आर एफ लि. ने आवेदन का स्पष्ट तौर पर समर्थन किया है। प्राधिकारी ने हुई क्षति का विश्लेषण करने और उत्पादन लागत, भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने समस्त हितबद्ध पक्षकारों को 5 अगस्त, 2009 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था। लिखित अनुरोधों/हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों पर दिए गए तर्कों पर इस जांच परिणाम में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है।
- x. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्टूबर, 2007 से 30 सितंबर, 2008 तक (जांच अवधि) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007, अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल है।
- xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान मामले में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था। प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में विधिवत विचार किया गया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है, जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।
- xiii. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना जुटाने से मना किया है अथवा वर्तमान जांच की कार्यवाई के दौरान आवश्यक सूचना को अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर यह जांच परिणाम दर्ज किया है।
- xiv. \*\*\* चिन्ह इस विवरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

#### 5. प्रकटन विवरण और प्राधिकारी द्वारा उसकी जाँच के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :-

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

- क) किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।
- ख) वर्तमान शुल्क के बावजूद आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- ग) वर्तमान शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है।
- घ) माप की एक इकाई और एक सीमाशुल्क वर्गीकरण को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
- ङ.) पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के रूप में (निर्धारित शुल्क के रूप में) की जाए जिसे प्रति टायर शुल्क के रूप में व्यक्त किया जाए।

### मै. एशियन्स रबर्स द्वारा किए गए निवेदन

- क) चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य मूल जाँच में उत्तर देने वाले उत्पादक के खपत संबंधी मानदंडों और अन्य लागत के आधार पर परिकलित होना चाहिए।
- ख) प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त विभिन्न कच्ची सामग्री पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्कों का समायोजन किया गया है अथवा नहीं।
- ग) चूँकि निर्यात कीमत डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर आधारित है अतः उसे हितबद्ध पक्षकारों से गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए।
- घ) प्रकटन विवरण में क्षति मार्जिन तथा वास्तविक आंकड़ों के परिकलन के लिए अपनाई गई पद्धति का उल्लेख नहीं किया गया है।
- ङ.) यदि संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया ही जाना हो तो इसे पिछले पैटर्न के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की निम्नानुसार जाँच की है :-

(क) जहाँ तक सीमाशुल्क वर्गीकरण और माप की इकाई के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी का यह मानना है कि वर्तमान परिणाम में पाटनरोधी शुल्क के कार्यान्वयन के मुद्दे को उठाया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्गीकरण के होते हुए भी विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।

(ख) जहाँ तक चीन के सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने के मुद्दे का प्रश्न है, प्राधिकारी के अनुसार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन के उत्पादकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग न करने का विकल्प चुना है, पिछली कार्यवाहियों में सहयोग करने वाले निर्यातकों के खपत संबंधी मानदंडों को अपनाना उचित नहीं होगा।

(ग) संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न कच्ची सामग्रियों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का समायोजन किया गया है अथवा नहीं, इस मुद्दे पर प्राधिकारी ने प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार किया है और इसलिए किसी भी मामले में यह भारत द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं है। जहाँ तक घरेलू उद्योग को क्षति का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की वास्तविक लागतों पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यह इस मूलभूत प्रश्न के प्रति पूर्वाग्रह से रहित है कि केवल भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण किए जाने से ही यह साबित नहीं होता कि भारत में उस निविष्टि की लागत निर्यातक देश से अधिक है।

(घ) जहाँ तक वास्तविक आंकड़ों के प्रकटन के मुद्दे का संबंध है; डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों पर आधारित निर्यात कीमत का प्रकटन किया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गोपनीय आंकड़ों का प्रकटन नहीं किया जा सकता जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी मामले में हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता का दावा किए जाने और प्राधिकारी द्वारा उससे गोपनीय समझे जाने की स्थिति में सूचना का प्रकटन नहीं किया जाएगा।

(ङ.) जहाँ तक शुल्क के पैटर्न के मुद्दे का संबंध है; यह नोट किया जाता है कि जाँच के दायरे में अलग-अलग और/अथवा किसी युग्म में आयातित ऐसे नॉन-रेडियल बायस टायर, ट्यूब और फ्लैप शामिल हैं जिनका इस्तेमाल बसों और लॉरियों (ट्रकों सहित) में किया जाता है। मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने यह तर्क भी दिया है कि चीन जन. गण. से आयातित टायर टायरों के आकार और विमा, अनुभागीय चौड़ाई, समग्र व्यास, थ्रेड, गहनता आदि में अंतर के कारण घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेचे गए टायरों के तुलनीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पीयूसी का आयात टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों के एक सेट अथवा पृथक-पृथक रूप से टायर/ट्यूब अथवा फ्लैप के रूप में किया जा सकता है; प्राधिकारी का यह विचार है कि यह विश्लेषण भार के आधार पर किया जाना अधिक समीचीन होगा। अतः पीयूसी के स्वरूप और जाँच की अवधि के दौरान हुए पीयूसी के आयातों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक/आयातक ने इस मध्यावधि समीक्षा जाँच में सहयोग नहीं किया है, यह विश्लेषण भार के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## 6. अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध:

मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि:

- समस्त संगत मापदंडों के निर्धारण हेतु मूल जाँच में समस्त सूचना टायर प्रति सैट के आधार पर प्रदान की गई थी जबकि घरेलू उद्योग ने वर्तमान समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद की इकाई में जानबूझकर परिवर्तन करते हुए उसे भार आधार पर दर्शाया है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद पण्य वस्तु है और इसकी बिक्री नगों/टायर सैट आधार पर की जाती है तथा मूल मामले के साथ उचित तुलना करने और किसी छेड़छाड़ से बचने के लिए एक समान मापदंडों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी को भार आधार पर सूचना प्रदान करने के बारे में याचिकाकर्ताओं के स्वैच्छिक विकल्प को अस्वीकार कर देना चाहिए जो सर्वथा अवैध एवं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के गुण-दोष से रहित है।

- मूल जांच में टायरों के बारे में शुल्क संरचना पर विचार कर उसका विश्लेषण किया गया था और उसे टायर प्रति सैट आधार पर अपनाया गया था न कि भार आधार पर । अतः वर्तमान समीक्षा मामले में शुल्क की गणना टायर प्रति सैट अथवा नग आधार पर की जानी चाहिए न कि प्रति कि.ग्रा. आधार पर ।

### घरेलू उद्योग के अनुरोध

घरेलू उद्योग ने इस बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं कि प्राधिकारी को संख्या/नगों के मुकाबले भार आधार पर समूची जांच क्यों करनी चाहिए । उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि:

- टायरों का उत्पादन और बिक्री अनेक आकारों में की जाती है । (इसने संख्या एवं भार में आकार वार उत्पादन प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न किया है) । यह देखा जा सकेगा कि टायरों के अलग-अलग आकार की संबद्ध लागत और कीमत में भारी अंतर है ।
- चीन की किसी भी कंपनी ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । ऐसी किसी स्थिति, जिसमें हितबद्ध पक्षकार सूचना जुटाने से मना करते हैं अथवा प्राधिकारी के साथ अन्यथा सहयोग नहीं करते हैं, उस स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः न्यायोचित हैं ।
- यद्यपि, टायरों के कई अलग-अलग आकार शामिल हैं और यहां तक कि एक आकार की लागत और कीमत अलग-अलग हो सकती है । तथापि, अलग-अलग आकारों के टायरों की लागत और कीमत टायरों के भार के काफी अधिक सीमा तक आनुपातिक होती है ।
- टायर बनाने की उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया जाए । यह देखा जाएगा कि टायरों की उत्पादन लागत में टायर के भार के अनुपात में अंतर होता है । यद्यपि, इस बात पर सहमति हो सकती है कि अंतिम बिक्री कीमत जटिल मापदंडों पर आधारित होती है; निर्विवाद रूप से टायरों की उत्पादन लागत कीमत शासित करने वाले कारकों में से एक है । इसके अलावा, उत्पादन लागत एवं परिणामी कीमतें भार के अनुसार घटती-बढ़ती हैं । दूसरे शब्दों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि टायरों की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत टायर के भार के अनुरूप होती हैं ।
- विचाराधीन उत्पाद में टायर, ट्यूब और फ्लैप्स शामिल हैं । इसके अलावा, इनकी बिक्री कई संयोजनों में अर्थात् (क) टायर, (ख) ट्यूब, (ग) फ्लैप, (घ) टायर एवं ट्यूब, (ङ) टायर एवं फ्लैप, (च) ट्यूब एवं फ्लैप तथा (छ) टायर, ट्यूब एवं फ्लैप में की जा सकती है ।

- पूर्ववर्ती जांचों के समय हितबद्ध पक्षकारों ने इस आशय का जोरदार तर्क दिया था कि टायरों के अलग-अलग आकारों को शामिल किए जाने के मद्देनजर प्रति टायर औसत कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना अनुचित है ।
- आवेदक द्वारा पूर्व में प्रदत्त आयात से संबंधित सूचना तथा डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई आयात संबंधी सूचना का अवलोकन किया जाए । यह देखा जाएगा कि कई सौदों में टायर के आकार का उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अलावा, यद्यपि, टायर के आकार का उल्लेख तो है तथापि, विशेष आकार में शामिल टायरों के कई अलग-अलग प्रकारों के कारण भार संख्या की तुलना में अधिक उचित आधार है ।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए समस्त सौदों की भारित औसत आयात कीमत पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत तथा अंतिम पाटन मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है। पूर्ण विवरण का उल्लेख न होने के कारण मात्र से कुछ सौदों को अलग रखना उचित नहीं होगा ।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने टायरों के प्रकारों के अलग-अलग आकारों के लिए एक बैंच मार्क की सिफारिश की थी । टायरों के अलग-अलग आकारों की लागत और कीमत में भारी अंतर होने के कारण टायरों के अलग-अलग आकारों के लिए एक बैंचमार्क कीमत हर हालत में नितान्त अनुचित है । स्थिति यह है कि कम आकार के मामले में शुल्क की अधिक राशि वसूली जाती है और उच्च आकार के मामले में शुल्क की राशि कम होती है ।
- वर्तमान जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच है । ऐसा मामला होने के कारण प्राधिकारी माप की उसी इकाई पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे पूर्ववर्ती जांच के समय अपनाया गया था ।
- टायरों के भार पर विचार करना हर हालत में अधिक वैज्ञानिक, सभी पक्षकारों के लिए उचित है और इससे खासकर चीन के उत्पादकों के असहयोग के मद्देनजर संख्या के संबंध में पाटन मार्जिन के निर्धारण की तुलना में पाटन मार्जिन का निर्धारण तथ्यपरक होगा ।
- ट्रक तथा बस के रेडियल टायरों से संबंधित जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया है । यद्यपि, इस बात पर सहमति है कि उक्त



मामले में जांच रेडियल टायर से संबंधित थी, तथापि यह नोट किया जाना चाहिए कि अन्यथा दोनों उत्पाद अत्यंत तुलनीय हैं ।

- वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संपूर्ण समीक्षा की है । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी मूल जांच की तुलना में माप की अलग इकाई को अपनाने में पूर्णतः न्यायोचित है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

- प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक सहित हितबद्ध पक्षकारों ने इस मध्यावधि समीक्षा जांच में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत अनुरोध किए हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद "बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम ब्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स " है तथा आगे यह नोट करते हैं कि जांच के दायरे में बसों तथा लारियों (ट्रकों सहित) में प्रयुक्त ऐसे गैर-रेडियल बायस टायर, ट्यूब और फ्लैप भी हैं जिनका आयात अलग-अलग किया गया हो और/अथवा उनके किसी संयोजन में ।
- जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा भार आधार पर किए गए मूल्यांकन/दावों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इससे हितबद्ध पक्षकारों के हितों की रक्षा के अधिकार का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं होता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने यह तर्क दिया है कि मध्यावधि समीक्षा जांच में मूल जांच की तुलना में अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई स्वेच्छिक अथवा अनपेक्षित परिवर्तन नहीं होना चाहिए । उन्होंने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद एक पण्य वस्तु उत्पाद है और उसकी बिक्री नगों/प्रति सैट आधार पर की जाती है न कि भार आधार पर । तथापि, उन्होंने यह अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. से आयातित टायर अलग-अलग आकार तथा टायरों के आयाम, खंड-वार चौड़ाई, समग्र ब्यास, धागे, गहराई आदि के कारण घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तथा बेचे जाने वाले टायरों से तुलनीय नहीं है ।
- आवेदक के विचारों सहित हितबद्ध पक्षकारों के विचारों का संज्ञान लेते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि विचाराधीन उत्पाद के आकार एवं अन्य भौतिक विशेषताओं के रूप में अंतर हो सकता है तथा आगे इस बात पर विचार करते हुए कि विचाराधीन उत्पाद का आयात टायर सैट, ट्यूब तथा फ्लैप के रूप में किया जा सकता है और इसका आयात टायरों/ट्यूबों अथवा फ्लैपों के रूप में अलग-अलग किया जा सकता है; प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के स्वरूप तथा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए गए आयातों के स्वरूप पर विचार करते हुए तथा इस बात पर भी विचार करते हुए कि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस मध्यावधि समीक्षा जांच में सहयोग नहीं किया

है, भार आधार पर विश्लेषण करना उचित माना जाता है। अतः समस्त आयात सौदों का विश्लेषण किया गया है और आयात की मात्रा का उल्लेख सार्थक विश्लेषण करने हेतु भार आधार पर किया गया है। तथापि, संभव सीमा तक क्षति विश्लेषण संख्या/नग आधार पर भी किया गया है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू "समान वस्तु"

### ग.1 आवेदक के विचार

7. वर्तमान समीक्षा जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि पूर्ववर्ती जांचों में परिभाषित किया गया है।
- (i) पूर्ववर्ती जांचों और वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद चीन तथा थाईलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित "बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम ब्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स " है। उत्पाद के दायरे में केवल बसों तथा लारियों (ट्रकों सहित) में प्रयुक्त गैर-रेडियल अथवा बॉयस टायर शामिल हैं, जो सीमाशुल्क अध्याय 40 के उपशीर्ष सं. 40112090 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं तथा ट्यूब एवं फ्लैप क्रमशः 40131020 तथा 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।
- (ii) मूल जांच और उत्पादित तथा इस समय विश्व भर में बेचे जा रहे उत्पाद के बीच उत्पाद की विशेषताओं में कोई खास परिवर्तन या विकास नहीं हुआ है।
- (iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित टायरों तथा संबद्ध देशों से निर्यातित टायरों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के मुद्दे की विस्तृत जांच की गई थी और यह माना गया है कि आयातित तथा घरेलू उत्पाद समान वस्तुएं हैं।

### ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन तथा एशियन रबड़ (इंडिया) ने अनुरोध दायर किए हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है। "घरेलू उद्योग" के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. यद्यपि, आवेदक ने एसोसिएशन की सत्यता को चुनौती दी है और यह दावा किया है कि उसके अनुरोधों को उसी आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि उक्त एसोसिएशन आयातकों या उपभोक्ताओं की एसोसिएशन नहीं है, तथापि, प्राधिकारी ने एसोसिएशन की चिंताओं का निवारण करना उचित समझा है।

पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान समीक्षा में समीक्षाधीन विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. तथा थाईलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित "बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम ब्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त

न्यूमेटिक नॉन रेडियल बाँयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स " है । जांच के दायरे में बसों तथा लारियों (ट्रकों सहित) में प्रयुक्त ऐसे गैर-रेडियल बायस टायर, ट्यूब और फ्लैप भी हैं जिनका आयात अलग-अलग किया गया हो और/अथवा उनके किसी संयोजन में ।

10. टायरों का उत्पादन मौटे तौर पर दो प्रकारों अर्थात् रेडियल तथा गैर रेडियल में किया जाता है । बसों और लारियों में प्रयुक्त ट्यूब तथा फ्लैप रहित या सहित रेडियल टायर वर्तमान जांच के दायरे में नहीं आते हैं । टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों का उत्पादन अलग-अलग किया जाता है; तथापि उनका ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में एक साथ अनिवार्य उपयोग किया जाता है । टायर सीमाशुल्क अध्याय सं. 40 के उप शीर्ष सं. 40112090 के अंतर्गत और ट्यूब तथा फ्लैप क्रमशः उपशीर्ष सं. 40131020 एवं 40129049 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं । तथापि, ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं । आवेदक के इस दावे का किसी हितबद्ध पक्षकार ने खंडन नहीं किया है कि मूल जांच और विचाराधीन उत्पाद तथा इस समय विश्व भर में बेचे जा रहे उत्पाद के बीच उत्पाद विशेषताओं में कोई खास परिवर्तन या विकास नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है । आवेदक के इस दावे का भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने खंडन नहीं किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है ।
11. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा चीन जन.गण. एवं थाईलैंड से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खराब अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित एवं संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल-बदल कर उपयोग किया है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा चीन जन.गण. एवं थाईलैंड से आयातित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तुएं माना जा रहा है ।

## घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र विस्तार

### घ.1 घरेलू उद्योग के विचार.

12. घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में आवेदक के अनुरोध निम्नानुसार हैं:
  - (i) भारत में लगभग 43 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकारों के टायरों के उत्पादन की क्षमता सृजित की है । तथापि, संबद्ध वस्तु का उत्पादन ए टी एम ए के 6 सदस्य कंपनियों तथा कुछ छोटी-मोटी कंपनियों द्वारा किया जाता है । अतः वर्तमान मामले के विधिक प्रावधानों तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भागीदार कंपनियों का उत्पादन मै. एम आर एफ लि. के समर्थन से भारतीय उत्पादन के 97.71% से अधिक बनता है और मै. एम आर एफ लि. के समर्थन के बिना यह भारतीय उत्पादन का 76.93% बनता है ।

- (ii) अपोलो, बिरला, सिएट, जे.के.टायर्स, एम आर एफ ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि वे ऐसी किसी कंपनी से संबद्ध नहीं हैं जो संबद्ध वस्तु की आयातक/निर्यातक है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके प्रतिकूल कोई आरोप नहीं लगाया है तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।
- (iii) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता है; और इस प्रकार यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है ।
- (iv) अतः घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि भागीदार कंपनियां पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" हैं ।

## घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन तथा एशियन रबड़ (इंडिया) ने अनुरोध दायर किए हैं । किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है । "घरेलू उद्योग" के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि भागीदार कंपनियों ने संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक मात्रा में आयात किया है और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाणिज्यिक मात्रा क्या है ।

## घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"ख" "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

15. पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और राशि में वृद्धि हेतु आवेदन संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में संलग्न सदस्यों की ओर से ए टी एम ए ने दायर किया है । संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में संलग्न ए टी एम ए के 6 सदस्य हैं, अर्थात् मै. अपोलो टायर्स लि., मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई), मै. एम आर एफ लि., मै. जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. गुडईयर इंडिया लि. । इन 6 सदस्यों में से मै. अपोलो टायर्स लि., मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई) तथा मै. जे.के.टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. ने अपेक्षितसूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जबकि मै. एम आर एफ लि. ने आवेदन का स्पष्ट तौर पर समर्थन किया है । भागीदार सदस्यों ने पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में परिवर्तित परिस्थितियों के संबंध में संगत सूचना प्रदान की है ।

16. चूंकि ए टी एम ए के भागीदार सदस्यों का हिस्सा भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 76.93% बनता है जो भारतीय उत्पादन में 50% हिस्से से अधिक है, इसलिए ये कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ "घरेलू उद्योग" हैं। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आवेदक मै. अपोलो टायर्स लि. मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (केसोराम इंडस्ट्रीज लि. की एक इकाई), मै. एम आर एफ लि. तथा मै. जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. ने प्राधिकारी के समक्ष पत्र दायर किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

## ड. पाटन मार्जिन

### ड.1 बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार-चीन जन.गण.

17. चूंकि इस मध्यावधि समीक्षा जांच में चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के दावे के बारे में कोई उत्तर तथा कोई अनुरोध दायर नहीं किया है, इसलिए चीन जन.गण. के समस्त निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश पर लागू नियमों के अनुसार किया जाए।

18. भारत तथा अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की जांच से संबंधित विभिन्न उद्घोषणाओं के आधार पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के बारे में निम्नलिखित विधि स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। यह अनुरोध किया गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक निम्नलिखित प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि नियमों में निर्धारित मापदंडों में से एक की भी पूर्ति नहीं होती है।
- सिद्ध करने का भार/दायित्व - चीन के प्रतिवादी निर्यातकों पर यह दायित्व है कि वे यह सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं।

- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समग्र समूह यह दावा न करे।

- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता कि रूपांतरण की प्रक्रिया दस्तावेज साक्ष्य के जरिए पूरी न की गई हो।

19. इस प्रकार चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत, तथा (ख) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकता है। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

## ड.2. निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. अनुरोध ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन तथा मै. एशियन रबड़ (इंडिया) द्वारा दायर किए गए हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है। मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने अपने अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ चीन के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु श्रीलंका को एक प्रतिनिधिक देश के रूप में लेने का सुझाव दिया है।

## ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. जहां तक श्रीलंका से आयात कीमत पर विचार करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि श्रीलंका से आयात सिएट लि. द्वारा किए जा रहे हैं और इसलिए आयात कीमत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह विश्वसनीय है। जहां तक श्रीलंका को एक उचित प्रतिनिधि देश मानने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने मूल जांच के समय श्रीलंका को एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में नहीं लिया था क्योंकि श्रीलंका को एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में लेना उपभोक्ताओं तथा निर्यातकों के लिए अलाभकारी माना गया था। इस प्रकार प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत स्वीकार की थी। इसके अलावा, प्राधिकारी के पास ऐसा कोई साक्ष्य/आंकड़ा नहीं है, जिन्हें श्रीलंका के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पर्याप्त माना जा सके।

22. अधिनियम की धारा 9 (1)(ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा

उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

किंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।"

23. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रदान करें। तथापि, चीन के किसी उत्पादन/निर्यातक की ओर से प्रश्नावलियों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

24. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपबंधित है कि:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत तथा डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इस अनुमान के खंडन के अधीन है ।

26. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।



27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरुआत संबंधी सूचना के बाद चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन करने की मांग नहीं की है। इसके अलावा चीन जन.गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के बारे में पर्याप्त साक्ष्य/आंकड़ों के साथ कोई उत्तर नहीं दिया है तथा कोई अनुरोध नहीं किया है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। आवेदक ने उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित भारत में वास्तविक रूप से संदेय कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का साक्ष्य प्रदान किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि चीन के उत्पादकों ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दावे का खंडन नहीं किया है और न ही किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले अन्य तीसरे देश का सुझाव दिया है; आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझा है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार निर्धारित उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा एक उचित लाभ मार्जिन हेतु समायोजित किया गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर संबद्ध वस्तु के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत मानदंड, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत तथा उचित लाभ पर चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु सामान्य मूल्य के परिकलन की दृष्टि से विचार किया गया है।

### ड.3. थाईलैंड के मामले में सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग के विचार

28. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। उन्होंने थाईलैंड में घरेलू बाजार में प्रचलित टायर की कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु उन्हें उनके घरेलू बाजार में टायरों की वास्तविक सौदे-वार बिक्री कीमत (एक उत्पादक तथा थोक व्यापारी/वितरक के बीच) के बारे में कोई उचित, अधिप्रमाणित तथा सही सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इस बात के मद्देनजर थाईलैंड में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक ने उत्पादन लागत के अनुमानों पर विचार किया है।

### ड.4. थाईलैंड के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

29. प्राधिकारी ने आवेदक ने इस दावे को नोट किया है कि उन्होंने थाईलैंड में घरेलू बाजार में प्रचलित टायर की कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु उन्हें उनके घरेलू बाजार में टायरों की वास्तविक सौदे-वार बिक्री कीमत के बारे में कोई उचित, अधिप्रमाणित तथा सही सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। थाईलैंड के किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और न ही थाईलैंड में लागत या कीमत के बारे में प्राधिकारी को कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराई गई है। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 क(1)(ग) (i) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने में समर्थ नहीं

है, जिसमें घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उत्पाद की कीमत के बारे में पर्याप्त सूचना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) (ii) (क) के अनुसार सामान्य मूल्य भी निर्धारित नहीं कर सकते जिसके अंतर्गत तीसरे देश को हुए निर्यातों के बारे में पर्याप्त सूचना अपेक्षित है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने लाभ मार्जिन सहित विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर थाईलैंड में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार चीन जन.गण. तथा थाईलैंड के निर्यातकों तथा उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

अम.डॉ./कि. ग्रा.	चीन जन.गण.	थाईलैंड
कच्ची सामग्री की लागत	****	****
परिवर्तन लागत	****	****
बिक्री, सामान्य व प्रशासनिक लागत	****	****
ब्याज	****	****
उत्पादन की संपूर्ण लागत	****	****
उचित लाभ	****	****
सामान्य मूल्य	3.25	3.29

#### ड. 5. निर्यात कीमत

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन तथा एशियन रबर (इंडिया) को छोड़कर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की कीमत के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आयात के आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और निर्यात कीमत को निर्धारित किया है।
31. भारत के लिए कारखाना निर्यात कीमत निकालने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा अंतरदेशीय भाड़े, हैंडलिंग, बीमा, विदेशी भाड़े एवं कमीशन के संबंध में दावा किए गए कीमत समायोजनों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. तथा थाईलैंड के सभी निर्यातकों अथवा उत्पादकों के लिए संबद्ध वस्तु की कारखाना निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की है :

		चीन जन.गण.	थाईलैंड
आयात मूल्य	मी.ट.	28,653	32

आयात मूल्य	लाख रुपए	18,898.37	36.67
सी आई एफ निर्यात कीमत	रू./कि.ग्रा.	65.96	114.04
परिवर्तन दर	रू./अम.डॉ.	41.08	41.08
सी आई एफ निर्यात कीमत अम.डॉ. में	अम.डॉ./किग्रा.	1.60	2.77
कीमत समायोजन (कुल)	अम.डॉ./किग्रा.	****	****
कारखाना निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	****	****

## ड 6. पाटन मार्जिन

### ड.6.1 घरेलू उद्योग के विचार:

32. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है अपितु काफी अधिक भी है जिससे भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

### 33. सतत पाटन तथा सतत पाटन की संभावना:

वर्तमान जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच है और निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन (वृद्धि) करना अपेक्षित है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू करने की जरूरत की जांच करना और इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की राशि को संशोधित करना अपेक्षित है । यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना अथवा उसके जारी रहने की जांच करना अपेक्षित नहीं है, तथापि आवेदक ने यह प्रदर्शित करने के लिए सूचना प्रदान की है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क में उचित वृद्धि न किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है । इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं-

(क) मूल जांचों की तुलना में निर्यात की मात्रा काफी अधिक बनी रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकेगा -

वर्ष	संबद्ध देशों से आयात (नग में )	मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में % के रूप में वृद्धि	स्रोत
2001-02	3,589		मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के अनुसार
2002-03	16,735		

2003-04	77,538		
अप्रैल 04-जून,05 (जांच अवधि)	2,16,851		
जांच अवधि वार्षिकीकृत	1,73,481		
2005-06	3,24,997	87.33	डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़े
2006-07	5,35,717	208.8	
2007-08	6,29,239	262.71	
अक्टू 07- सितं. 08 (जांच अवधि)	5,42,380	212.65	

आवेदक ने यह तर्क दिया है कि मूल जांच और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

(ख) अत्यधिक पाटन स्तरों पर शुल्क लगाए जाने के बावजूद लगातार हो रहे निर्यातों से स्पष्टतः यह पता चलता है कि बैचमार्क में बढ़ोत्तरी करने की जरूरत है ।

#### ड.10.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:

34. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन और उसकी सततता के बारे में अपने दावों की पुष्टि करते हुए कोई सूचना प्रदान नहीं की है ।

#### ड.11. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के समान स्तर पर एक उचित तुलना होनी चाहिए; अतः प्राधिकारी ने कारखाना स्तर पर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत दोनों का निर्धारण किया है । यह नोट किया गया है कि उत्पाद का आयात टायर ट्यूब एवं फ्लैप सैट, (टी टी एफ) अथवा टायर एवं ट्यूब सैट (टी टी) अथवा केवल टायर/ट्यूब या फ्लैप के रूप में किया जाता है । उपर्युक्त दर्ज कारणों से प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारित औसत सामान्य मूल्य तथा भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण समस्त आयातों को भार में परिवर्तन करने के बाद किया है । बिक्री की स्थितियों और शर्तों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । वर्तमान मामले में संबद्ध देशों के किसी निर्यातक/उत्पादक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे किसी संभावित कारक का उल्लेख नहीं किया है जिससे तुलनीयता प्रभावित हो सकती हो । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि की गई तुलना एक उचित तुलना है । उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार बनता है :-

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	थाईलैंड
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./कि.ग्रा.	****	****
निर्यात कीमत	अम.डॉ./कि.ग्रा.	****	****
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./कि.ग्रा.	****	****
पाटन मार्जिन	%	113-118	20-25

प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों देशों के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

## च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण

### च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

36. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात जारी है;
- मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है;
- घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है ;
- घरेलू उद्योग उस सीमा तक अपना निष्पादन सुधारने में समर्थ नहीं रहा है जितनी उसके पास है;
- क्षतिकारी पाटन की रोकथाम हेतु पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्तर काफी अपर्याप्त है;
- वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाना अपेक्षित है।

### च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

37. ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन तथा एशियन रबड़ (इंडिया) ने अनुरोध किए हैं कि किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अन्य अनुरोध दायर नहीं किया है। संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है और न ही किसी निर्यातक से क्षति एवं कारणात्मक संबंध सहित वर्तमान जांच के किसी पहलू के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है।

मै. एशियन रबड़ (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ ये तर्क दिए हैं कि:

- घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका अधूरी तथा अर्ध समर्थित है।

- विगत में कच्ची सामग्री की उच्च कीमत, जो अब नहीं है. के आधार पर अधिक पाटनरोधी शुल्क की मांग करने के लिए वर्तमान जांच अवधि का चयन करना घरेलू उद्योग का जानबूझकर किया गया एक प्रयास है ।
- याचिकाकर्ता क्षति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने अथवा यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि पाटन से उद्योग की रक्षा हेतु बैचमार्क कीमत, पर्याप्त नहीं है ।
- अनुरोधों के बावजूद घरेलू उद्योगों ने अन्य अनुरोधों के अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी के बीच हुए पत्र व्यवहार का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध नहीं कराया । कंपनी ने मूल जांच से लेकर जांच की वर्तमान अवधि तक निर्धारित प्रात्र में निष्पादन से संबंधित सूचना दायर करने के बारे में घरेलू उद्योग के लिए निर्देश की मांग की ।
- घरेलू उद्योग ने विधि शास्त्र के ज्ञात सिद्धांतों के विरुद्ध अपने विरोधियों अथवा प्रतिवादी पक्षकारों को अपने विवेकाधिकार से चुनने का प्रयास किया । ऐसी किसी प्रस्तावित कार्यवाई से प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के पास अपने विचार प्रस्तुत करने तथा कार्यवाई में भाग लेने और घरेलू उद्योग के दावों का विरोध करने का अधिकार होता है । यही कारण है जिससे कि आयातकों तथा अन्य व्यापार निकायों द्वारा पूर्व में अपने अभ्यावेदन क्यों नहीं प्रस्तुत किए जा सके ।
- सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु रबड़, कच्चे तेल की कीमतों सहित कच्ची सामग्री की कीमत में संभावित वृद्धि हेतु याचिकाकर्ता की कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसकी तुलना वर्ष 2001-02 की अवधि के दौरान मौजूद कीमतों के स्तर से की गई है जबकि निश्चयात्मक शुल्क वर्ष 2007 में लागू किया गया था । वर्ष 2007-08 के लिए कच्ची सामग्री की कीमत संबंधी विवरण से उससे अधिक कीमत का पता चलता है जिसमें अब काफी गिरावट आ गई है ।
- उत्पाद शुल्क में समान दर से 4% की कमी किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है । इसके अलावा कच्ची सामग्री की कीमत में आई गिरावट से ही घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत कम हुई है ।
- घरेलू उद्योग यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में प्रभावित हुआ है जिनमें बैचमार्क शुल्क को बढ़ाना अपेक्षित है ।
- डॉलर के रूप में मौजूदा शुल्क से घरेलू उद्योग को वास्तविक अपेक्षा से अधिक संरक्षण मिला है । अमरीकी डॉलर में घट-बढ़ तथा रूपए में 25-30% तक की कमजोरी जो अमरीकी डॉलर की तुलना में हासित बनी हुई है, के कारण घरेलू उद्योग को ज्यादा सुरक्षा मिली है ।
- चीन जन.गण. से आयातित टायर विनिर्माण नुस्खे एवं भौतिक विशेषताओं के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं विक्रीत टायरों से तुलनीय नहीं है । चीन जन.गण. से आयातित टायर अतिरिक्त रबड़ से बने उच्च अभियांत्रित टायरों तथा अधिक भार ले जाने के लिए तैयार किए गए टायरों की तुलना में कम आकार के आयाम वाले घटिया गुणवत्ता के हैं ।

- याचिका के अगोपनीय रूपांतरण के अलावा, आयातकों को कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे वे प्रभावित अभ्यावेदन करने से वंचित हुए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रश्नावली का उत्तर, क्षति संबंधी सूचना, पाटनमार्जिन, निर्यात कीमत, प्रति सैट आधार पर सामान्य मूल्य आयातक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।
- प्राधिकारी ने अपने जांच परिणाम में टायरों के आकार को भी जांच के दायरे में लाना उचित समझा। अनुरोध है कि उत्पाद के दायरे को टायरों के आकार सहित मूल जांच में निर्धारित उत्पाद के दायरे तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों का मूल्यांकन और जांच प्रति सैट आधार पर की जानी चाहिए। प्राधिकारी को निवल बिक्री प्राप्ति, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता तथा क्षमता उपयोग पर विचार करने के लिए सुसंगत कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए।
- मूल जांच में विरोधी पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि जांच में भागीदार कुछेक भारतीय विनिर्माता चीन के निर्यातकों से संबद्ध हैं। इसका साक्ष्य भी प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया था। कंपनियों ने सीमित गुणवत्ता नियंत्रण और चीन में रह रहे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में अपने खुद के ब्रांड से टायरों का विनिर्माण करवाने हेतु चीन के उत्पादकों/निर्यातकों से कार्यनीतिक समझौता किया है। न केवल अपोलो अपितु सिएट तथा जे के इंडस्ट्रीज जैसे अन्य भारतीय उत्पादकों ने भी चीन की लागत मित्वययी उत्पादन प्रौद्योगिकी का भारी लाभ उठाने के लिए ऐसे उद्यमों में प्रवेश किया है।
- निर्यातक सहित विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एक अपील दायर की गई है जो सेस्टेट में लंबित है। घरेलू उद्योग के आधार का निर्धारण चीन के निर्यातकों के साथ उसके संबंध पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।
- उत्पादन में प्रयुक्त रबड़ तथा कच्ची सामग्री अलग-अलग ग्रेडों की होती है और उसकी लागत ग्रेड-दर-ग्रेड आधार पर काफी भिन्न होती है। कच्ची सामग्री के विशेष ग्रेड के उपयोग से टायर की अंतिम कीमत निर्धारित होती है। घरेलू उद्योग द्वारा विशिष्टता टायरों का उत्पादन किया जा रहा है जबकि संबद्ध देशों से निर्यातित टायर घटिया गुणवत्ता के हैं और उन्हें उस स्थिति में तैयार किया जाता है जहां निष्पादन कोई खास महत्व नहीं रखता है। इस प्रकार लागत में कटौती हुई है, जिसके बारे में अधिकांश भारतीय उत्पादकों ने गौर नहीं किया है। इसी वजह से घरेलू कीमतें अधिक रही हैं और चीन के टायरों की कीमत कम रही है।
- घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि शुल्क लगाने के बाद आयातों में वृद्धि हुई है जिसके बारे में घरेलू उद्योग ने प्रतिकूल आंकड़े दिए हैं।
- अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का तात्पर्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, अपितु उचित कीमत पर उसका आयात करना है। अतः यह तर्क देना कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात हो रहे हैं, आधारहीन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

- घरेलू उद्योग के आरोप के विपरीत जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों में भारी गिरावट आई है और आयात कीमत में भी कमी आई है जिससे यह पता चलता है कि अपाटित कीमतों पर आयात सुनिश्चित करने के लिए अपने वर्तमान स्वरूप में पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त से अधिक है ।
- कच्ची सामग्री कीमत में गिरावट आने और रूपए के मूल्य में 25% का ह्रास होने के कारण मौजूदा बेंचमार्क शुल्क काफी अधिक है । इसके अलावा, शुल्क लागू न होने की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा कीमत में वृद्धि किए जाने से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई कीमत वृद्धि संबद्ध वस्तु के आयात के कारण बाधित नहीं हुई है ।
- घरेलू उद्योग सहित विभिन्न कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से उत्पाद के संबद्ध बाजार में लाभ का पता चलता है ।
- जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत तथा बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई । लाभ में गिरावट का कारण संबद्ध वस्तु के आयात को नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके बीच और अब घरेलू उद्योग के बीच अंतर कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद पर्याप्त बाजार हिस्सा रखने के लिए बेहतर है ।
- विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है । क्षमता उपयोग में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है , रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है । मालसूची में वृद्धि हुई है परंतु इसे क्षति के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें निर्यात बिक्री भी शामिल है । इससे संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का पता नहीं चलता है ।
- कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री दोनों समनुरूप हैं और ये 40-50% के बीच रही हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्र प्राप्ति और क्षति रहित कीमत समान हैं । इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत पर बिक्री कर रहा है और उसे कोई क्षति नहीं हो रही है ।
- चीन जन.गण. से आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । घरेलू उद्योग ने बिक्री एवं उत्पादन में वृद्धि करके अपना बाजार हिस्सा पर्याप्त रूप में बनाए रखा है । उपभोक्ताओं ने भी चीन से आयातों का सहारा नहीं लिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जन.गण. से हुए आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

ऑल इंडिया टायर्स डीलर्स फेडरेशन ने अपने अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार उल्लेख किया है :

- इन टायरों के आयात पर सितंबर/अक्टूबर, 2007 से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और संदर्भ कीमत नियत किए जाने के बाद प्रमुख टायर निर्माताओं द्वारा कीमत में भारी वृद्धि की गई है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमत (प्राकृतिक रबर तथा पेट्रो उत्पाद आधारित निविष्टि दोनों) में बढ़ोत्तरी हुई है । परंतु बाद में जब कच्ची सामग्री कीमत घटकर पिछले पांच वर्षों के स्तर पर आ गई तो घरेलू टायर निर्माताओं के बर्चस्व के कारण कीमतों में तदनुसार कमी नहीं की गई है ।



- इस बीच अम. डॉ. की तुलना में भारती रुपए का मूल्यहास हुआ है, जिसकी वजह से पिछले दो वर्षों में आयात 25% - 30% तक महंगे हो गए हैं। इस प्रकार इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के रूप में नाइलोन फैब्रिक ट्रक/बस टायरों के आयातों से संरक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यह परीक्षा की घड़ी है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन तथा थाईलैंड से हुए टायरों के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त करना चाहिए और घरेलू सड़क परिवहन उद्योग तथा टायर व्यापार की बाजारी शक्तियों की मुक्त भूमिका का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए। इससे घरेलू टायर समूह की अविवेकपूर्ण कीमत नीतियों पर कुछ अंकुश लगेगा तथा ग्राहकों को मदद मिलेगी एवं आवश्यक वस्तुओं की दुलाई लागत में कमी आएगी।

### च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- जहां तक आवेदन में कथित त्रुटियों/अपूर्णता का संबंध है, प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच स्थिति में शुरू करना अपेक्षित है जब आवेदन में समीक्षा को आवश्यक सिद्ध करने वाली परिवर्तित परिस्थितियों का पर्याप्त साक्ष्य निहित हो। प्राधिकारी के लिए पूर्ण सूचना अपेक्षित नहीं है जैसी कि जांच की शुरुआत के चरण पर अंतिम निर्धारण हेतु अपेक्षित होती है।
- जहां तक जांच अवधि के चयन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की कीमत में परिवर्तन के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा उस स्थिति में न्यायोचित है जब पाटनरोधी शुल्क पूर्ववर्ती मामले में की गई संस्तुति के अनुसार हो। मूल जांच के समय घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा ली गई जांच अवधि के बाद निविष्टि की कीमत में वृद्धि के आधार पर बेंचमार्क पर उर्ध्वगामी संशोधन की दलील दी थी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान प्रचलित प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत पर सुसंगत विचार किया है।
- जहां तक बेंचमार्क शुल्क की पर्याप्तता का संबंध है, जांच से यह सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन काफी अधिक है।
- जहां तक जांच की शुरुआत से पूर्व घरेलू उद्योग तथा विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त पत्रों का संबंध है, यह आवेदन घरेलू उद्योग ने दायर किया है जो जांच की शुरुआत का आधार है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाद में किए गए सभी अनुरोधों का प्रकटन पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किया गया है।
- जहां तक पक्षकारों की भागीदारी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष जांच में भाग लेते हैं। घरेलू उद्योग यह तय नहीं कर सकता कि हितबद्ध पक्षकार कौन होना चाहिए और किसे उत्तर देना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को नियमों में परिभाषित किया गया है और प्राधिकारी ने सम्स्त हितबद्ध पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान किया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि किसी भी आयातक या उपभोक्ता या विदेशी उत्पादक ने प्रश्नावली का

उत्तर दायर नहीं किया है । मै. एशियन रबड़ ने भी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है । तथापि, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर ध्यान दिया है ।

- जहां तक कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के बारे में घरेलू उद्योग के गलत दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने वर्तमान जांच में समस्त मापदंडों का पुनर्निर्धारण किया है । इसके अलावा, आवेदक ने परिवर्तित परिस्थितियों के अपने दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए क्षति अवधि तथा जांच अवधि हेतु सूचना प्रदान की है । तथापि, इसका यह अर्थ नहीं निकलता है कि कीमत में वृद्धि पर वर्तमान जांच अवधि और मूल जांच के आधार वर्ष की कीमत के बीच विचार किया गया है ।
- जहां तक उत्पाद शुल्क में कमी के कारण लाभप्रदता में आए सुधार का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भाधीन अवधि में घरेलू उद्योग की वास्तविक लाभप्रदता पर विचार किया गया है जिसमें उत्पाद शुल्क का आरोपित प्रभाव भी शामिल है यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाए तो उसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्तमान जांच में पाई गई लाभप्रदता से अत्यधिक प्रतिकूल रही होती यदि भारत सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी नहीं की गई होती ।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि डी जी ए डी की वैबसाइट पर उपलब्ध मध्यावधि समीक्षा के निर्धारित प्रपत्र में भी ऐसे कुछेक कारकों को स्पष्टतः सूचीबद्ध किया गया गया है जो परिवर्तित परिस्थितियों को इंगित करते हैं और जिसमें क्षति रहित कीमत, सामान्य मूल्य, आयातों की पहुंच कीमत आदि में परिवर्तन शामिल है, जिसकी वजह से समीक्षा आवश्यक है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन मापदंडों में से किसी एक मापदंड में हुए किसी परिवर्तन से भी समीक्षा की जरूरत सिद्ध करने का पर्याप्त आधार बन जाता है । वर्तमान मामले में आवेदक ने समीक्षा की जरूरत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की है ।
- जहां तक विनिमय दर में परिवर्तन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में प्रचलित वास्तविक विनिमय दर पर वर्तमान जांच में विचार किया गया है ।
- जहां तक आयातित टायर और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त टायरों की अतुलनीयता के कथित दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की पुष्टि नहीं की गई है । प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के जरिए समस्त संगत साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं ।
- जहां तक इस मध्यावधिक समीक्षा जांच का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसके लिए जांच अवधि के दौरान विभिन्न मापदंडों की जांच करना अपेक्षित होता है । आवेदक के दावों का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस बात की किसी भी हालत में पुष्टि नहीं की गई है कि वर्तमान स्थिति पाटनरोधी स्थिति की राशि में परिवर्तन करने या उसकी अवधि बढ़ाने के लिए न्यायोचित नहीं है ।
- जहां तक इस जांच के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का संबंध है, प्राधिकारी का मत यह है कि पूर्ववर्ती जांच में विचाराणीय उत्पाद चीन जन.गण. तथा थाईलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित "बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम ब्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त

न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स " है इसलिए इस जांच का क्षेत्र वहीं रहता है ।

- जहां तक चीन के उत्पादकों के साथ भारतीय उत्पादकों अथवा भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों के संबंध का मामला है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है और आवेदक द्वारा दायर पत्रों के अनुसार मै. अपोलो टायर्स लि., मै. सिएट लि., मै. बिरला टायर्स (कैसोराम इंड लि. की एक इकाई), मै. एम आर एफ लि., मै. जे.के.टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि वे चीन जन.गण. तथा थाईलैंड में उत्पाद के किसी उत्पादक-निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंध नहीं हैं ।
- जहां तक घरेलू उद्योग के इस दावे का संबंध है कि शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में यह दावा किया है कि आयात कीमत इस प्रकार से समायोजी रही है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा धीरे-धीरे बढ़कर शून्य हो गई है । घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयात कीमत के समायोजन के बाद देश में उत्पाद का भारी मात्रा में आयात जारी है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद के आयात सतत पाटित कीमतों पर जारी हैं जिससे घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है । इसके अलावा, ये कीमतें घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम रही हैं ।
- वर्तमान आयातों के संबंध में प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के साथ इस बात से सहमत हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, तथापि घरेलू उद्योग का तर्क यह है कि सूचित आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और इनसे घरेलू कीमतों पर भारी कटौती हुई है । इसके अलावा, क्षति मार्जिन भी काफी अधिक है ।
- जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित न करने वाले आंकड़ों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मध्यावधि जांच में घरेलू उद्योग का दावा यह है कि वर्तमान शुल्क पूर्व में पुष्टिकृत क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है । घरेलू उद्योग ने शुल्क के स्वरूप और उसकी मात्रा में संशोधन करने के लिए कहा है ।
- जहां तक लाभ प्रदर्शित करने वाली वार्षिक रिपोर्टों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना में वित्तीय घाटा प्रदर्शित नहीं होता है । तथापि, वित्तीय घाटे की मौजूदगी शुल्क में संशोधन की एक पूर्वापेक्षा नहीं है । वस्तुतः क्षति विश्लेषण करते समय इस बात से सहमत होना पड़ता है कि कानून के अंतर्गत उल्लिखित कारकों की सूची न तो व्यापक है और न ही इससे एक या अनेक कारकों से अनिवार्यतः निर्णायक मार्गदर्शन प्राप्त होता है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क की राशि में इस आधार पर वृद्धि तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए दायर किया है कि इस स्थिति से सतत पाटन हो रहा है और यह राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
- जहां तक लागत और कीमत का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उत्पादन लागत तथा बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई है; तथापि, जहां उत्पादन लागत में हुई

वृद्धि वर्ष 2007-08 तक बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम रही है वहीं जांच अवधि में बिक्री प्राप्ति में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम रही है ।

- प्राधिकारी ने क्षति मापदंडों की जांच की है और निर्धारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर आधारित है । इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान जांच एक मध्यावधिक समीक्षा जांच के स्वरूप की है, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद एक या अधिक मापदंडों में सुधार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का परिणाम हो सकता है । तथापि, वर्तमान आवेदन शुल्क के स्वरूप और उसकी मात्रा में इस आधार पर परिवर्तन करने के लिए है कि वर्तमान शुल्क अपर्याप्त है और इससे उत्पाद का सतत पाटन हो रहा है ।
- प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आयात की मात्रा में वृद्धि किसी मध्यावधि समीक्षा में एक पूर्वापेक्षा नहीं है । पाटित कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पाद का सतत आयात जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है और क्षति मार्जिन आदि सकारात्मक है, यह मत तय करने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान शुल्क में संशोधन करना अपेक्षित है ।
- प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि मै. एशिया रबड़ (इंडिया) ने यह बताया कि वे चीन के और भारतीय टायरों के बीच आयामी तुलना उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन वह प्राप्त नहीं हुई है ।
- प्राधिकारी ने इस तर्क को नोट किया है कि अम.डॉ. की तुलना में भारतीय रूपए के मूल्य में ह्रास हुआ है जिससे पिछले दो वर्षों में आयात 25%-30% तक महंगे हो गए हैं । प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि जहां तक इस मध्यावधि समीक्षा जांच का संबंध है, वह जांच अवधि के दौरान प्रचलित समस्त कारकों पर विधिवत विचार करेंगे ।

38. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती ।

39. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार प्रावधान है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों;

घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

40. प्राधिकारी ने क्षति जांच से संबंधित तर्कों को नोट किया है और उठाए गए मुद्दों का उचित स्थानों पर समाधान किया है। प्राधिकारी ने तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है।

41. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी एवं पाटन तथा क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की जा सके। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है :-

क. मूल्य प्रभाव

क) मांग का निर्धारण

42. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है, जिसका सारांश निम्नानुसार है:

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	18,224	29,481	36,419	28,685
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	5,977	2,814	1,110	422
कुल आयात	मी. ट.	24,201	32,295	37,529	29,107
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	387,561	419,173	434,772	460,038
अन्य उद्योग की बिक्री	मी. ट.	128,262	134,222	142,252	135,121
मांग	मी. ट.	540,024	585,690	614,553	624,266

संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात	नग	306,122	452,028	471,394	504,169

अन्य देशों से आयात	नग	113,738	48,476	20,632	6,607
कुल आयात	नग	419,860	500,504	492,026	510,776
घरेलू उद्योग की बिक्री	नग	6,743,169	7,249,446	7,710,366	8,188,490
अन्य उद्योग की बिक्री	नग	2,420,029	2,532,485	2,683,995	2,549,444
मांग	नग	9,583,058	10,282,435	10,886,387	11,248,710

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है और इसमें भार तथा संख्या/नगों, दोनों रूप में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आधार वर्ष क तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि भार के रूप में लगभग 15.60% तथा संख्या/नगों के संबंध में लगभग 17.38% रही थी।

ख) आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

43. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-ii (ii) में यह उपबंध है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ..." इस प्रकार पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

दोनों देशों से हुए आयातों की मात्रा निम्नानुसार रही थी:

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
➤ चीन जन.गण.	मी.ट.	17,155	29,265	36,406	28,653
➤ थाईलैंड	मी.ट.	69	216	13	32
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	17,224	29,481	36,419	28,685
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	5,977	2,814	1,110	422
कुल आयात	मी.ट.	24,201	32,295	37,529	29,107
आयातों का हिस्सा					
➤ चीन जन.गण.	%	72.12	90.62	97.01	98.44

➤ थाईलैंड	%	3.18	0.67	0.03	0.11
संबद्ध देशों से आयात	%	75.80	91.29	97.04	98.55
अन्य देशों से आयात	%	24.70	8.71	2.96	1.45
भारत में उत्पादन की तुलना में आयात					
➤ चीन जन.गण.	%	2.84	4.64	5.42	4.26
➤ थाईलैंड	%	0.125	0.034	0.002	0.005
भारत में खपत					
➤ चीन जन.गण.	%	3.23	5.00	5.92	4.59
➤ थाईलैंड	%	0.142	0.037	0.002	0.005

## संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
➤ चीन जन.गण.	नग	292,922	448,113	471,331	503,723
➤ थाईलैंड	नग	13,200	3,915	63	446
संबद्ध देशों से आयात	नग	306,122	452,028	471,394	504,169
अन्य देशों से आयात	नग	113,738	48,476	20,632	6,607
कुल आयात	नग	419,860	500,504	492,026	510,776
आयातों का हिस्सा					
➤ चीन जन.गण.	%	69.77%	89.53%	95.79%	98.62%
➤ थाईलैंड	%	3.14%	0.78%	0.01%	0.09%
संबद्ध देशों से आयात	%	72.91%	90.31%	95.81%	98.71%
अन्य देशों से आयात	%	27.09%	9.69%	4.19%	1.29%
भारत में उत्पादन की तुलना में आयात					
➤ चीन जन.गण.	%	2.53%	3.77%	3.72%	3.97%
➤ थाईलैंड	%	0.114%	0.033%	0.000%	0.004%

भारत में खपत					
➤ चीन जन.गण.	%	3.06%	4.36%	4.33%	4.48%
➤ थाईलैंड	%	0.138%	0.038%	0.001%	0.004%

उपर्युक्त के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

(क) आधार वर्ष की तुलना में चीन से हुए उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है । यद्यपि वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान भार के रूप में गिरावट आई है ।

(ख) थाईलैंड से हुए आयातों में भार तथा संख्या/नगों के संबंध में आधार वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है । यद्यपि, वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में जांच अवधि में मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन वो अभी भी काफी कम है ।

(ग) यद्यपि, संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, तथापि, चीन जन.गण. से हुए आयातों में आधार वर्ष की तुलना में भार एवं संख्या/नगों, दोनों की तुलना में भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है ।

#### ख. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

44. घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का कीमत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अत्यधिक सीमा तक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती । कीमत कटौती की सीमा का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति का आकलन समस्त रिबेट और करों को घटाने के बाद किया गया था। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना लागू पाटनरोधी उपाय पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई थी । लागू सीमा शुल्क सहित संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति तथा क्षति रहित कीमत से काफी कम है । स्पष्टतः चीन के निर्यातकों ने पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात जारी रखा है , जिसका पता खासकर इस संदर्भ में कि पाटनरोधी उपाय पहले से ही लागू हैं, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के रूप में चलता है ।

भार के रूप में

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.	थाईलैंड	संबद्ध देश
सी आई एफ कीमत	रू./किग्रा.	65.96	114.04	66.01
पहुंच प्रभार	रू./किग्रा.	0.66	1.14	0.67
निर्धारणीय मूल्य	रू./किग्रा.	66.62	115.18	66.68



सीमा शुल्क	%	10.00	10.00	10.00
मूल सीमा शुल्क	रु./किग्रा.	6.66	11.52	6.67
सीमा शुल्क पर उपकर	रु./किग्रा.	0.20	0.35	0.20
सी वी डी पर उपकर	रु./किग्रा.	0.33	0.57	0.33
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	73.15	126.47	73.21
पाटनरोधी शुल्क बैचमार्क	रु./किग्रा.	100.91	100.91	100.91
संदेय ए डी डी	रु./किग्रा.	27.76	-	27.70
ए डी डी के साथ पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	100.91	126.47	100.91
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	****	****	****
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	****	****	****
कीमत कटौती	%	85-90	5-10	85-90
ए डी डी के साथ कीमत कटौती	रु./किग्रा.	****	****	****
ए डी डी के साथ कीमत कटौती	%	32-37	5-10	32-37

### कीमत हास/न्यूनीकरण

45. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का हास/न्यूनीकरण हुआ है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि (अक्टू '07-सितं. '08)
उत्पादन की लागत	रु./किग्रा.	100.00	111.30	115.81	128.63
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	100.00	111.96	119.65	125.60

आयातों का पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	46.26	68.66	65.51	73.21
□ चीन जन.गण.	रु./किग्रा.	46.25	68.73	65.44	73.15
□ थाईलैंड	रु./किग्रा.	46.53	59.33	282.06	126.47
परिवर्तन					
उत्पादन की लागत	रु./किग्रा.		11.30	4.50	12.83
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.		11.96	7.69	5.95
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.		22.40	(3.15)	7.69
□ चीन जन.गण.	रु./किग्रा.		22.48	(3.29)	7.71
□ थाईलैंड	रु./किग्रा.		12.80	222.74	(155.60)

### घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

46. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

### उत्पादन, बिक्री क्षमता तथा क्षमता उपयोग

47. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति निम्नानुसार रही है :-

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	443,613	477,177	501,548	506,341
उत्पादन	मी.ट.	447,512	468,842	487,353	482,887
क्षमता उपयोग	%	100.88	98.25	97.17	95.37
बिक्री	मी.ट.	387,561	419,173	434,772	460,038
मांग	मी.ट.	540,024	585,690	614,553	624,266

संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
क्षमता	Nos	8,612,867	9,147,251	9,894,774	10,020,180
उत्पादन	Nos	8,688,566	8,987,470	9,598,703	9,556,049
क्षमता उपयोग	%	100.88	98.25	97.01	95.37
बिक्री	Nos	6,743,169	7,249,446	7,710,366	8,188,490
मांग	Nos	9,583,058	10,282,435	10,886,387	11,248,710

यह नोट किया जाता है कि:

(क) क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग ने क्षमता जोड़ी है। यह नोट किया जाता है कि मांग में लगभग 15.60% (भार के रूप में) की वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग ने लगभग 14.14% की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है। संख्या के रूप में क्षमता में लगभग 16.34% की अतिरिक्त वृद्धि की तुलना में मांग में लगभग 17.38% की वृद्धि हुई है।

(ख) आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 तक भार एवं संख्या/नगों के रूप में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई। तथापि, जहां मांग में लगभग 15.60% (भार के रूप में) और लगभग 17.38% (संख्या/नगों के रूप में) वृद्धि हुई, वहीं उत्पादन में केवल 7.90% (भार के रूप में) और 9.98% (संख्या/नगों के रूप में) वृद्धि हुई। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग संवर्धित क्षमता की सीमा तक और मांग में वृद्धि की सीमा तक अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ रहा है।

(ग) घरेलू उद्योग की बिक्री में भार और संख्या/नगों, दोनों रूप में वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद अपनी बिक्री मात्रा को सुधारने में समर्थ रहा है। घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि सतत पाटन न हुआ होता तो बिक्री के आगे और वृद्धि हुई होती और यह कि आयातों में वृद्धि होने के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा में बिक्री नहीं हो सकी।

लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह

48. लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह में घट-बढ़ निम्नानुसार रही है:

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ/हानि	रु./कि.ग्रा.	100.00	125.19	197.01	64.55
ब्याज पूर्व लाभ/हानि	रु./कि.ग्रा.	100.00	119.82	170.89	79.92
निवेश पर आय	%	100.00	120.46	163.21	73.67
नकद लाभ	रु./कि.ग्रा.	100.00	120.72	179.86	86.91

संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ/हानि	रु./सेट	100.00	126.95	195.68	60.86
ब्याज पूर्व लाभ/हानि	रु./सेट	100.00	118.18	173.90	80.54
निवेश पर आय	%	100.00	120.46	163.21	73.67
नकद लाभ	रु./सेट	100.00	119.14	183.18	87.57

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वर्ष 2007-08 तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भार तथा संख्या/नगों के संबंध में सुधार हुआ है। तथापि, जांच अवधि में लाभप्रदता में आधार वर्ष से भी कम गिरावट आई। इसके अलावा कर पूर्व लाभ एवं ब्याज पूर्व लाभ, दोनों में यही प्रवृत्ति दिखाई दी। लगाई गई पूंजी पर आय एवं नकद लाभ में लाभ के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। लगाई गई पूंजी पर आय एवं नकद लाभ में वर्ष 2007-08 तक सुधार हुआ परंतु जांच अवधि में तेजी से गिरावट आई। समस्त घरेलू उत्पादक बहु उत्पाद कंपनियां हैं और कंपनी के नकद प्रवाह की स्थिति से संबद्ध उत्पाद की

स्थिति का पता नहीं चलेगा । अतः प्राधिकारी ने इन वर्षों के दौरान नकद लाभ की जांच की है जिसे ऊपर दर्शाया गया है ।

50. प्राधिकारी ने क्षति अवधि की तुलना में उत्पादन लागत एवं बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों में विचार करने के बाद लाभप्रदता की जांच की । यह पाया गया है कि समूची क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत एवं बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई । तथापि, जहां बिक्री कीमत में वृद्धि वर्ष 2007-08 तक उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से अधिक रही, वहीं उत्पादन लागत में वृद्धि जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से काफी अधिक रही थी । परिणामतः जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई ।

भार के रूप में (सूचीबद्ध)

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
उत्पादन की लागत	रु./किग्रा.	100.00	111.30	115.81	128.63
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	100.00	111.96	119.65	125.60
लाभ/हानि	रु./किग्रा.	100.00	125.19	197.01	64.55
वृद्धि					
उत्पादन की लागत	रु./किग्रा.		100.00	39.85	113.56
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.		100.00	64.35	49.78

संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
उत्पादन की लागत	रु./सेट	100.00	111.59	113.52	126.77
बिक्री कीमत	रु./सेट	100.00	112.31	117.40	123.66
लाभ/हानि	रु./सेट	100.00	126.95	195.68	60.86
वृद्धि					
उत्पादन की लागत	रु./सेट		100.00	16.70	114.30
बिक्री कीमत	रु./सेट		100.00	41.32	50.82

### बाजार हिस्सा

51. घरेलू उत्पादकों की बिक्री और संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना से यह पता चलता है कि यद्यपि भागीदार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है, तथापि, आधार वर्ष

की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि होने के कारण समग्र भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है।

भार के रूप में

बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	71.77	71.57	70.75	73.69
अन्य भारतीय उत्पादक	%	23.75	22.92	23.15	21.64
कुल भारतीय उद्योग	%	95.52	94.49	93.89	95.34
संबद्ध देशों से आयात	%	3.37	5.03	5.93	4.60
अन्य देशों से आयात	%	1.11	0.48	0.18	0.07

संख्या/नगों के रूप में

बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	70.37	70.50	70.83	72.79
अन्य भारतीय उत्पादक	%	25.25	24.63	24.65	22.66
कुल भारतीय उद्योग	%	95.62	95.13	95.48	95.46
संबद्ध देशों से आयात	%	3.19	4.40	4.33	4.48
अन्य देशों से आयात	%	1.19	0.47	0.19	0.06

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :-

भार के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	नग	100	104	112	112
मजदूरी	लाख रुपए	100	111	121	131
प्रति इकाई मजदूरी	रु./किग्रा.	100	105	111	121
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	100	100	95	95

## संख्या/नगों के रूप में

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	नग	100	104	112	112
मजदूरी	लाख रुपए	100	111	121	131
प्रति इकाई मजदूरी	रु./सेट	100	105	194	156
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	नग	100	99	97	92

52. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समस्त घरेलू उत्पादक बहु उत्पाद कंपनियों हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योग के रोजगार एवं प्रदत्त मजदूरी वर्तमान मामले में क्षति के मूल्यांकन का एक सही मापदंड नहीं हो सकती है ।

मालसूची

53. घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
औसत मालसूची	मी.ट.	100	122	140	189
बिक्री दिवसों की संख्या के रूप में स्टॉक	दिवस	100	108	125	158

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आने की आशा थी परंतु मालसूची में वृद्धि हुई है । इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग बाजार में संवर्धित उत्पादन की बिक्री करने में समर्थ नहीं रहा है ।

वृद्धि

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2007-08 तक घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी । तथापि, जांच अवधि के दौरान यह वृद्धि लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय के संबंध में नकारात्मक हो गई और जांच अवधि में मालसूची में प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, यद्यपि यह उत्पादन और बिक्री मात्रा के संबंध में सकारात्मक थी ।

55. सतत पाटन एवं क्षति की संभावना

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बेंचमार्क के वर्तमान स्तर पर आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत एवं क्षतिरहित कीमत से कम है ।

- ख. क्षति अवधि के तुलना में चीन जन.गण. से उत्पादों के आयातों में भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान आयात मात्रा में कुछ गिरावट आई, तथापि आयात की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान अभी भी उच्चतर स्तर पर है। वर्ष 2007-08 की तुलना में आयात में गिरावट आई परंतु यह लागू पाटनरोधी उपाय के कारण भी हो सकती है।
- ग. यद्यपि, क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता और बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ में गिरावट आई है। पाटित कीमतों पर हुए आयातों के परिणामस्वरूप कीमत कटौती, कीमत में ह्रास हुआ है और कम कीमत पर बिक्री भी हुई है। घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है।

### क्षति के बारे में निष्कर्ष

56. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मापदंडों से सामूहिक तथा संचयी रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हालांकि क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री जैसे मात्रात्मक मापदंडों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है, तथापि इसमें भारत में संबद्ध वस्तु की खपत में हुई बढ़ोत्तरी के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान स्पष्ट तौर पर सतत पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

### कारणात्मक संबंध

#### 57. घरेलू उद्योग के विचार

- क. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति चीन और थाईलैंड से पाटित आयातों के कारण हुई है। अन्य देशों से आयात न्यूनतम है। याचिकाकर्ता कंपनियां पिछले कई वर्षों से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। विनिर्माण प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। वस्तुतः उत्पादन प्रौद्योगिकी पूर्णतः परिपक्व, स्थापित एवं मानकीकृत है और इसमें अत्यंत कम प्रौद्योगिकीय नवीकरण तथा विकास हुए हैं। पाटन को छोड़कर इस क्षति का कोई अन्य कारण नहीं है।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत से काफी कम है जिससे कीमत में भारी कटौती हुई है। आयातों में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद कीमत में सकारात्मक कटौती के कारण हुई है।
- ग. सकारात्मक कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत की सीमा तक अपनी कीमत बढ़ाने से वंचित हुआ है। अतः सतत पाटित आयातों से कीमत में लगातार कटौती हो रही है।
- घ. सकारात्मक कीमत कटौती के कारण नगों के रूप में आयात मात्रा में वृद्धि हुई। परिणामतः पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक (वस्तुतः वृद्धि) बना रहा और भारतीय उत्पादकों के हिस्से में गिरावट आई। कीमत में भारी अंतर के कारण आयात मात्रा में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग आयातों की सीमा तक अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने से वंचित हुआ।
- ङ. घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में संबद्ध देशों से शुल्क प्रदत्त आयातित कीमत से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर को जोड़ने के बाद भी आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।



- च. घरेलू उद्योग पर संबद्ध आयातों के कीमत ह्रासकारी एवं न्यूनकारी प्रभाव की वजह से क्षति अवधि की तुलना में लाभप्रदता में गिरावट आई और निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह में परिणामी गिरावट आई ।
- छ. ऐसी स्थिति में जब निर्यातक पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भारत में भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से इस मात्रा में सर्वाधिक वृद्धि होगी ।
- ज. संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रहा है । वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कीमत में और अधिक कटौती होगी । इस प्रकार, संभावित शुल्क समाप्ति से कीमत में भारी कटौती और कम कीमत पर बिक्री होगी ।
- झ. आयातों के कारण कीमत कटौती जारी है । परिणामतः आयातों की मात्रा और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई । इसका प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई ।
1. आयातों एवं बाजार हिस्से में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित परिणामी कीमतों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप लाभ/हानि की स्थिति, आर ओ आई और नकद प्रवाह में आगे और गिरावट आई जिससे यह संकेत मिलता है कि सतत संबद्ध आयातों की स्थिति में घरेलू उद्योग की हालत खराब बनी रहेगी ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

58. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया गया था ।
- क. तीसरे देशों से आयात :- अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात नगण्य हैं अथवा न्यूनतम सीमा से कम हैं । इस प्रकार यह प्रतीत नहीं होता है कि अन्य देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।
- ख. मांग में कमी :- यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है; इस प्रकार मांग में संभावित कमी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है ।
- ग. खपत की पद्धति :- खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया है । घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामग्री के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा कर रहा है । संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि प्रदर्शित हुई है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि खपत की पद्धति से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।
- घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां :- रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।
- ङ. प्रौद्योगिकी विकास:- रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार क्षति अवधि की तुलना में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।
- च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन :- घरेलू उद्योग के निष्पादन को घरेलू बिक्री तथा निर्यात बिक्री की दृष्टि से अलग-अलग किया गया है ; और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु घरेलू उत्पादकों के केवल घरेलू निष्पादन पर ही विचार किया गया है ।
- छ. उत्पादकता :- यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है ।
59. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है । इसकी स्पष्ट तौर पर पुष्टि निम्नलिखित द्वारा होती है :-

- i. संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से काफी कम है जिससे कीमत में भारी कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि की सीमा तक उच्चतर बिक्री प्राप्ति हासिल करने में समर्थ नहीं रहा है ।
  - ii. उपर्युक्त स्थिति से कीमत ह्रास भी हुआ है जिससे लाभ एवं निवेश पर आय में गिरावट आई है ।
  - iii. पाटित आयातों के कारण हुई कीमत कटौती और कीमत ह्रास से घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत प्राप्त करने से वंचित हुआ है ।
60. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पटित नियम 11 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।
- घ. पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना**
61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीन जन.गण. और थाईलैंड से पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है । अतः पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की आगे जांच अपेक्षित नहीं है ।
- ड. निष्कर्ष**
62. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों अथवा उपर्युक्त जांच परिणाम में अन्यथा दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान पाटन तथा क्षति की स्थिति एवं पाटन तथा क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
- i. संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक तथा न्यूनतम निर्धारित सीमा से ज्यादा है । संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जारी है ।
  - ii. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर प्रवेश होने की संभावना है ।
  - iii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति में आगे और गिरावट आई है । इसके अलावा, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसमें बढ़ोत्तरी होने की संभावना है ।
  - iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है ।
  - v. सतत पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के निवारण हेतु पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करना अपेक्षित है ।

**च. सिफारिशें**

63. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है, वर्तमान पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की जरूरत की पुष्टि होती है, घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है तथा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन तथा आयातों के कारण क्षति जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का मत यह है कि इस उपाय में विस्तार करना अपेक्षित है और निम्नलिखित शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संबद्ध देशों से हुए आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन अपेक्षित है। क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है।

64. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन, जो भी कम जो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समस्त आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि और पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

	शीर्ष / उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1.	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स	थाईलैंड	थाईलैंड	कोई	कोई	0.37	मी.ट	अम.डॉ.
2.	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स	थाईलैंड	थाईलैंड से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	0.37	मी.ट	अम.डॉ.
3	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित	उन देशों से इतर अन्य कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	थाईलैंड	कोई	कोई	0.37	मी.ट	अम.डॉ.

		नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स							
4.	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	1.64	मी.ट	अम.डॉ.
5.	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स	चीन जन.गण. जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.64	मी.ट	अम.डॉ.
6.	40112090 , 40131020 एवं 40129049	बसों तथा लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक के सामान्य रिम व्यास कोड वाले ट्यूब और/अथवा रबड़ फ्लैप सहित या रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक नॉन रेडियल बॉयस टॉर, ट्यूब एवं फ्लैप्स	उन देशों से इतर अन्य कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	चीन जन.गण.	कोई	कोई	1.64	मी.ट	अम.डॉ.

65. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3, 8, 1, 9 और 9 के अंतर्गत लागू शुल्क को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं;

66. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2010

**Subject: Mid-Term Review investigation regarding anti-dumping duty imposed on imports of 'Bias Tyres for Bus and Lorries/Trucks' originating in or exported from China PR and Thailand – Final Findings.**

**No. 15/1/2009-DGAD.**—Whereas the Designated authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules); recommended imposition of Anti Dumping duty on the imports of "new/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries) falling under Sub-heading 40112090, 40131020 and 40129049 respectively. The final findings were notified vide Notification No 14/9/2005-DGAD dated 19<sup>th</sup> June 2007 and definitive anti dumping duty was imposed vide Notification No. 88/2007-Customs dated 24<sup>th</sup> July 2007.

2. The Authority received a duly substantiated application from Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) for review and enhancement of anti-dumping duty in force and modification in the form of duty, *inter alia*, based on the grounds that the existing duty is not sufficient to address the injury to the domestic industry. The Applicant submitted prima facie evidence in this regard, requesting for review and enhancement of the anti dumping duty in force.

3. Having satisfied itself that the applicant has produced sufficient positive information substantiating the need for a review, the Authority initiated the mid-term review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Notification No. 15/1/2009-DGAD dated 27<sup>th</sup> February, 2009 in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules.

**B. PROCEDURE**

4. In these proceedings the procedure described below has been followed:

- i. The Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Designated Authority sent copies of initiation notification dated 27<sup>th</sup> February 2009 to the Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic

industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassies of the subject countries along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time.

- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- iv. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
1.	<i>Qingdao Zhongce Rubber Co., China PR</i>
2.	<i>Shanghai Tyre &amp; Rubber Co., China PR</i>
3.	<i>Aeolus Tyre Co.Ltd., China PR</i>
4.	<i>Quingdao Monolith OTR Tire Co.Ltd., China PR</i>
5.	Yokohama Tire manufacturing (Thailand) Company, Ltd., Thailand
6.	Thai Bridgestone Co. Ltd., Thailand
7.	Otani Tire Co. Ltd., Thailand
8.	Michelin Siam Co. Ltd., Thailand

M/s Thai Bridgestone Co. Ltd. in its communication stated that they do not export the subject goods to India and do not also intend to export the same in future. M/S Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. stated that they did not export the subject goods to India during the year 2005 to 2009. Barring these two companies, no other exporter has responded to the questionnaires in response to the above notification.

Questionnaires were sent to the following known importers and users of the subject goods in India for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Company's Name
1.	Radials International, New Delhi
2.	Kartar Tyre House, New Delhi
3.	Kaks & Bills Pvt. Ltd., New Delhi
4.	Rana Tyres, New Delhi
5.	Sunny International, Mumbai
6.	Aman International, Mumbai
7.	Vikas Road Carriers Ltd, Bharuch, Gujarat
8.	AAA Impex, Coimbatore, Tamil Nadu

In response to the above notification, only All India Tyre Dealers Federation, an association, claiming to be an association of tyre dealers of the subject goods, responded in the instant matter. No user or importer has filed response to the questionnaire.

- vi. The imports data for the period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- vii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- viii. As stated, the application for mid-term review was filed by ATMA. There are six members of ATMA engaged in the manufacturing of the subject goods, namely M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.), M/s MRF Ltd., M/s JK Tyre & Industries Ltd. and M/s Goodyear India Ltd. M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.) and M/s JK Tyre & Industries Ltd. have submitted the information/data for undertaking injury analysis, whereas M/s MRF Ltd. has expressly supported the application. The Authority examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the injury suffered and to work out the cost of production, cost to make and sell the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- ix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 5<sup>th</sup> August 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this finding.
- x. The period of investigation for the purpose of the present review is 1<sup>st</sup> Oct 2007 to 30<sup>th</sup> September 2008 (POI). However, injury analysis covered the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and the POI.
- xi. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant matter were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement have been duly considered in these findings.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xiii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xiv. \*\*\* In this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

5. **Submissions made by the interested parties in response to the Disclosure statement and examination thereof by the Authority**

The following submissions have been made by the interested parties in response to the Disclosure statement:

**Submissions made by the domestic industry**

- a) None of the interested parties have co-operated with the Authority
- b) The volume of imports has significantly increased despite current duties.
- c) Domestic industry is continuously suffering injury despite current duties.
- d) One unit of measurement and one customs classification needs to be specified
- e) The anti dumping duty may be recommended in terms of fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty per tyre. The duty may be recommended in terms of US\$.

**Submissions made by M/s. Asian Rubbers**

- a) The normal value of China PR should be on the basis of the consumption norms and other cost of producer who had responded in the original investigation.
- b) It is unclear from the disclosure statement that whether the antidumping duties imposed on various raw materials used to produce the subject goods has been adjusted or not.
- c) Since the export price is based on DGCIS data, the same should not be kept confidential from the interested parties.
- d) The disclosure statement is silent about the methodology used for calculating injury margin and actual figure.
- e) if at all the anti dumping duty is to be levied on the subject goods, the same should be in the earlier pattern.

**Examination by the Authority**

The Authority has examined the issues raised by the interested parties in response to the Disclosure statement as follows:

- (a) As regards the issue of Customs classification and unit of measurement is concerned, the Authority is of the view that implementation of anti dumping duties is not required to be addressed in the present findings. It is, however, clarified that anti dumping duty shall apply on imports of the product under consideration irrespective of classification.
- (b) As regards the issue of determination of Normal value of China PR is concerned, the Authority is of the view that considering the fact that the Chinese producers have chosen not to co-operate with the Authority, it would not be appropriate to



adopt the consumption norms of the exporters who had cooperated in the previous proceedings.

- (c) As regards the issue of the antidumping duties imposed on various raw materials used to produce the subject goods has been adjusted or not; the Authority has considered international price of input raw materials and therefore, the same in any case is unaffected by the anti dumping duties imposed by India. As regards injury to the domestic industry, the Authority is required to consider actual costs of the domestic industry. This is without prejudice to the fundamental question that merely because anti dumping duties have been imposed by India, the same does not imply that the cost of that input in India is higher than the exporting country.
- (d) As regards the issue of disclosure of actual figures; the export price based on DGCIS data has been disclosed. However, the Authority notes that confidential data cannot be disclosed as Rule 7 of the AD Rules clearly proscribe disclosure of any information wherein confidentiality has been claimed by an interested party and treated so by the Authority.
- (e) As regards the issue of pattern of duty; it is noted that the scope of investigation includes such non-radial bias tyres, tubes and flaps used in buses and lorries (including trucks) whether imported individually and/or in any combination thereof. M/s. Asian Rubber (India) has also contended the tyres imported from China PR are not comparable to the once manufactured and sold by the domestic industry on account of differences in size and dimension of the tyres, sectional width, overall diameter, thread, depth etc. Besides, considering that the PUC could be imported either as a set of tyres, tubes, and flaps or could as well be imported separately as tyres / tubes or flaps; the Authority considers that it would be more prudent to undertake the analysis on weight basis. Thus, considering the nature of PUC and the nature of imports of the PUC effected during the POI, and also considering the fact that no exporter/producer from the subject countries has co-operated in this mid-term review investigation it is deemed appropriate to undertake the analysis on weight basis.

#### **6. Submissions of Interested parties in respect of the methodology to be adopted**

**M/s Asian Rubber (India)** has, *inter alia*, contended that:

- All the information was provided on tyre per set basis in the original investigation for determination of all relevant parameters whereas there is an arbitrarily change in the unit of the product under consideration by the domestic industry in present review application on weight basis. As the Product under consideration is merchandisable and sold in piece/ tyre set basis, and in order to have a fair comparison with the original case and to avoid any manipulation, the use of similar parameters is very important. The Authority should reject the arbitrary choice of the petitioners to provide the same on weight basis, which is entirely illegal and devoid of merits in the facts and circumstances of the case.
- The duty structure in the original investigation on tyres was considered, analyzed and adopted on the tyre per set basis and not on weight basis. In the present review case therefore, duty should be calculated on the basis on tyre per set or piece basis and not on per kg basis.

### **Submissions of the domestic industry**

The domestic industry has made the following submissions as to why the Authority should undertake the entire examination on weight basis as against the numbers/pieces. It has, *inter alia*, contended that:

- Tyres are produced and sold in a large number of sizes. (It enclosed a statement showing size-wise production in number and weight). It would be seen that there are significant differences in the associated costs and prices of different size of tyres.
- None of the Chinese companies have responded to the Authority. In a situation where interested parties refuse access to or otherwise does not cooperate with the Authority, the Designated Authority is fully justified to proceed with best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.
- Even when a large number of different sizes of tyres are involved and even when one size may have different costs and prices, costs and prices of tyres of different sizes are to a very significant extent proportional to the weight of the tyres.
- Production process of making tyres may kindly be referred. It would be seen that the cost of production of tyres varies in proportion to the weight of tyre. While it is appreciated that the eventual selling prices are based on consideration of a complex parameters; undisputedly cost of production of the tyres is one of the governing factors for the prices. Further, cost of production and consequential prices move in the same direction as the weight. In other words, it can be concluded that cost of production and selling price of tyres move in tandem with tyre weight.
- Product under consideration includes tyres, tubes, and flaps within the scope of the product under consideration. Further, these may be sold in a variety of combinations, such as (a) tyre, (b) tube, (c) flap, (d) tyre & tube, (e) tyre and flap, (f) tube and flap, and (g) tyre, tubes and flaps.
- At the time of previous investigations, interested parties strongly argued that determination of dumping margin on the basis of average price per tyre was incorrect in view of inclusion of different sizes of tyres.
- Imports information earlier provided by the Applicant and the imports information made available by the DGCI&S may kindly be referred. It would be seen that tyre size has not been mentioned in a large number of transactions. Further, even when tyre size is mentioned, given a number of different types of tyres involved in particular size, weight is more appropriate basis as compared to number.
- The Designated Authority is required to determine export price and eventually dumping margin after considering weighted average import price of all

transactions. It would not be appropriate to exclude some transactions merely because full description is not mentioned.

- The Designated Authority had recommended one benchmark for different sizes of tyres. Given significant difference in the cost and price of different sizes of tyres, one benchmark price for different sizes of tyres in any case is highly inappropriate. Situation is leading to collection of higher quantum of duty in case of lower size and lower duty in case of higher sizes.
- The present investigation is a mid-term review investigation. Such being the case, it is not obligatory for the Authority to consider the same unit of measures as was adopted at the time of previous investigation.
- Considering the weight of tyres in any case is much more scientific, fair to all parties and will lead to objective determination of dumping margin as compared to determination of dumping margin in terms of numbers, particularly in view of non-cooperation by the Chinese producers.
- In the investigations relating to truck & bus radial tyres, the Designated Authority has adopted weight as the unit of measurement. While it is appreciated that the investigations in that case relate to radial tyres, nevertheless, it must be noted that otherwise the two products are quite comparable.
- Present investigation is a mid-term review investigation. The Designated Authority has conducted full review. Therefore, the Designated Authority would be fully justified to adopt different unit of measurement, as compared to original investigation.

### **Examination by the Authority**

- The Authority notes that Interested Parties including the Applicant have made detailed submissions regarding the methodology to be adopted in this mid-term review investigation. The Authority notes that Product under consideration is "new/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" and further notes that the scope of investigation includes such non-radial bias tyres, tubes and flaps used in buses and lorries (including trucks) whether imported individually and/or in any combination thereof.
- As regards assessments/claims made by the domestic industry on weight basis, the Authority notes that the same does not in any way vitiate the rights of interested parties to defend their interests. The Authority notes that M/s. Asian Rubber (India) has contended that there should not be any arbitrary and unwarranted change in the methodology adopted in the mid-term review investigation vis-à-vis the original investigation. It has been contended by them that the PUC is merchandisable product and sold on Pieces/ per set basis and not on weight basis. However, it has been further submitted by them that the tyres imported from China PR are not comparable to the once manufactured and sold

by the domestic industry on account of differences in size and dimension of the tyres, sectional width, overall diameter, thread, depth etc.

- Taking cognizance of the views of the interested parties including that of the Applicant and considering that there could be differences in terms of sizes and other physical characteristics of the PUC and further considering that the PUC could be imported either as a set of tyres, tubes, and flaps or could as well be imported separately as tyres / tubes or flaps; the Authority considers that it would be more prudent to undertake the analysis on weight basis. Thus, considering the nature of PUC and the nature of imports of the PUC effected during the POI, and also considering the fact that no exporter/producer from the subject countries has co-operated in this mid-term review investigation it is deemed appropriate to undertake the analysis on weight basis. Therefore, all import transactions have been analysed and import volumes have been expressed on weight basis for undertaking a meaningful analysis. However, to the extent feasible the injury analysis has been done on number/piece basis as well.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC 'LIKE ARTICLE'**

### **C.1 VIEWS OF THE APPLICANT**

7. Present review investigation being a mid-term review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations.
- (i) The product under consideration in the previous investigations and the present review is "new/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" originating in or exported from China and Thailand. The scope of the product includes only non-radial or bias tyres used in buses and lorries (including trucks), classified in Chapter 40 under customs subheading no. 40112090 and tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively.
- (ii) There is no material change or development in the product characteristics between the original investigation and product being produced and sold world-over at present.
- (iii) The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product. There is no known difference in tyres produced by the Indian industry and tyre exported from subject countries. The issue of product under consideration and like article was examined in detail by the Designated Authority in the original investigations and it has been held that the imported and domestic products are like article.

### **C.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties**

8. The submissions have been filed by All India Tyre Dealers Federation and Asian Rubber (India). No other interested party has filed any submissions. None of the interest parties have made any submission in respect of "domestic industry".

### **C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

9. Even though the applicant has challenged veracity of the association and claimed that its submissions should not be accepted on the grounds that the said association is not an

association of importers or consumers, the Authority has considered it appropriate to address the concerns of the association.

The product under consideration in the previous investigation that is being reviewed in the present review is "new/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" originating in or exported from China PR and Thailand. The scope of investigation includes such non-radial bias tyres, tubes and flaps used in buses and lorries (including trucks) whether imported individually and/or in any combination thereof.

10. Tyres are broadly produced in two types, namely radial and non-radial. Radial Tyres used in buses and lorries with or without tubes and flaps are beyond the scope of the present investigation. The tyres, the tubes and the flaps are produced separately; however, they are invariably used together in automotive applications. The tyres are classified in Chapter 40 under Customs sub-heading no. 40112090 and the tubes and the flaps are classified under sub-heading nos. 40131020 and 40129049 respectively. However, Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of investigation. The claim of the Applicant that there is no material change or development in the product characteristics between the original investigation and product being produced and sold world-over at present, has not been disputed by any interested party. The goods produced by the domestic industry are being considered as like articles to the imported subject goods. The claim of the Applicant that there is no known difference in the goods produced by the Indian industry and the subject goods exported from subject countries to India has also not been disputed by any interested party.
11. On the basis of information available on record, it is noted that there is no significant difference in the goods produced by the Indian industry and subject goods exported from China PR and Thailand. The goods produced by the Indian industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Thus, the goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from China PR and Thailand are being treated as like articles in accordance with the AD Rules.

#### **D. Scope of the Domestic Industry**

##### **D.1 Views of the domestic industry**

12. The submissions of the Applicant with respect to its claim of domestic industry are as under:
  - (i) There are approximately 43 companies in India who created capacity for the production of various kinds of Tyres. However, the subject goods are produced by the six ATMA member companies and some small non-member companies. Therefore, having regard to the legal provisions and facts & circumstances of the present case, the production by the participating companies command more than 97.71% of Indian production with the support of M/s MRF Ltd., and 76.93% of Indian production without the support of M/s MRF Ltd.

- (ii) Apollo, Birla, Ceat, JK Tyres, MRF have certified that they have not imported the subject goods from the subject countries during the POI. They have also certified that they are not related to a company who is a importer/exporter of the subject goods. None of the interested parties have either alleged or provided any evidence to the contrary.
- (iii) The domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 percent of total production of the like articles produced by the domestic producers; and hence the application has been made by or on behalf of the domestic industry.
- (iv) Domestic industry therefore submits that the Participating companies constitute “domestic industry” within the meaning of the AD Rules.

## **D.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties**

13. The submissions have been filed by All India Tyre Dealers Federation and Asian Rubber (India). No other interested party has filed any submissions. None of the interest parties have made any submission in respect of “domestic industry”.

M/s Asian Rubber (India) has, *inter alia*, contended that the participating companies have imported tyres from the subject goods in commercial volumes and they do not explain what constitutes commercial volume.

## **D.3 Examination by the authority**

14. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

*“‘domestic (b) industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry”.*

However, post initiation, this Rule has been amended as follows:

*“‘domestic (b) industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers only”*

15. The Application for review and enhancement of anti-dumping duty has been filed by ATMA on behalf of its members engaged in the manufacturing of the subject goods. M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.), M/s MRF Ltd., M/s JK Tyre & Industries Ltd., M/s Goodyear India Ltd. are the members of ATMA engaged in the manufacturing of the subject goods. Among these six members, M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.), M/s JK Tyre & Industries Ltd. have submitted the requisite

information/data; whereas M/s MRF Ltd. has expressly supported the application. The participating members have provided the relevant information in respect of changed circumstances with regard to dumping and consequent injury to the domestic industry.

16. As the participating members of ATMA hold 76.93% share of domestic production of subject product in India, which is more than 50% share in Indian production, these companies constitute the 'domestic industry' for the purpose of the present investigation within the meaning of the AD Rules. The Authority further notes that the Applicant M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.), M/s MRF Ltd., M/s JK Tyre & Industries Ltd, have filed letters with the Authority , inter alia, stating that they have not imported the subject goods during the POI.

## **E. DUMPING MARGIN**

### **E.1 Views of the domestic industry on Market Economy Treatment - China PR**

17. Since in this mid-term review investigation, none of the exporters/producers from China PR has responded and filed any submission with regard to their claim of market economy treatment, the normal value may be determined for all exporters/producers from China PR as per Rules applicable for non-market economy country.
18. Based on various pronouncements relating to examination of market economy status by India and other investigating authorities, following jurisprudence clearly emerge with regard to non-market economy status. It is submitted that market economy status cannot be granted unless the responding exporters satisfy each & every of the following conditions:
  - Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity,
  - Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values,
  - Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards,
  - Market economy status cannot be granted even if one of the parameters laid down in the Rules is not satisfied.
  - Onus/obligations - it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
  - Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
  - Market economy status cannot be granted unless the process of transformation has been completely established through documentary evidence.
19. The normal value in China PR can thus be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and

administrative expenses and profit. The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

**E.2. Views of exporter/importers and other interested parties**

20. The submissions have been filed by All India Tyre Dealers Federation and M/s Asian Rubber (India). No other interested party has filed any submissions. M/s Asian Rubber (India), in its submissions has, *inter alia*, suggested adopting Sri Lanka as the surrogate country for determining the Normal value for the Chinese exporters/producers.

**E.3. Examination by the Authority**

21. As regards the consideration of the import prices from Sri Lanka is concerned, the Authority notes that the imports from Sri Lanka are being made by CEAT Ltd and therefore the import prices itself cannot be considered, unless it is established that the same is reliable. As regards the consideration of Sri Lanka as an appropriate surrogate country, the Authority notes that the Authority did not adopt Sri Lanka as an appropriate surrogate country at the time of original investigation as the adoption of Sri Lanka as an appropriate surrogate country was found to be disadvantageous to the consumers and exporters. Thus, the Authority had adopted cost of production in India duly adjusted to determine the Normal value. Moreover, the Authority does not have any evidence/data that could be deemed be sufficient to determine the normal value on the basis of Sri Lankan data.
22. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for the consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
  - (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
    - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
    - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

23. The Authority sent questionnaire to the known exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, no response has been received to the questionnaires from any of the Chinese producer/exporter.



24. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

25. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.

26. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:-

a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

27. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; none of the Chinese producers/exporters have submitted any response including the market economy questionnaire response and sought to rebut the non-market economy

presumption. Further, none of the exporter/producer from China PR or other interested parties have responded and made any submissions with sufficient evidence / data with regard to appropriate market economy third country. Thus, it is not possible to determine the Normal value on the basis of prices or value in the market economy third country. The Applicant has provided evidence of normal value, considering the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin. Having regard to the information on record and considering that the Chinese producers have not rebutted the claim of non-market economy, nor suggested any other appropriate market economy third country; the importers, consumers and other interested parties have also not provided any evidence in this regard, the Authority has considered it appropriate to determine normal value on the basis of “any other reasonable basis”. The Authority has therefore proposed to determine normal value on the basis of best estimates of cost of production, considering the information made available by the domestic industry. The cost of production so determined has been adjusted for selling, general & administrative expenses and a reasonable profit margin. Thus, the raw materials for manufacturing the subject goods at the international price, the consumption norms of the domestic industry, conversion costs of the domestic industry and reasonable profit have been considered for constructing the normal value for all exporters/producers of China PR.

### **E.3. Views of Domestic Industry on Normal value in case of Thailand**

28. It has been contended by the Applicant that the producers from Thailand are dumping subject goods in India. Efforts were made by them to obtain information about the prices of tyres prevailing in the domestic market in Thailand; but no reasonable, authentic and accurate information could be obtained by them about the actual transaction-wise selling price of tyres (between a producer and wholesaler dealer/distributor) in their domestic market. In view of the same, the applicant has considered estimates of the cost of production to determine normal value in Thailand.

### **E.4. Normal Value in respect of exporters/ producers from Thailand**

#### **Examination by the Authority**

29. The Authority has noted that Applicant's claim that efforts were made by them to obtain information about the prices of subject goods prevailing in the domestic market of Thailand and that no reasonable, authentic and accurate information could be obtained by them about the actual transaction-selling price of subject goods in their domestic market. None of the Thai exporters/producer filed the questionnaire response, nor any other information has been made available to the Authority with regard to costs or prices in Thailand. Under such circumstances, the Authority is not able to determine normal value in accordance with Section 9A (1) (c) (i) of the Act, which requires sufficient information with regard to the price of the product in the domestic market in the ordinary course of trade. Besides, the Authority cannot also determine normal value in accordance with Section 9A (1)(c)(ii)(a) of the Act, which requires sufficient information on exports to third country. Under these circumstances, the Authority has determined normal value in Thailand on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted to include a profit margin. Thus, the Normal values in respect of exporters/ producers from China PR and Thailand have been determined as follows:

US\$/kg	China PR	Thailand
Raw materials costs	****	****
Conversion cost	****	****
Selling, general & administrative costs	****	****
Interest	****	****
Full cost of production	****	****
Reasonable profit	****	****
<b>Normal value</b>	<b>3.25</b>	<b>3.29</b>

### E. 5. Export price

30. The Authority notes that except for the Applicant, All India Tyre Dealers Federation and Asian Rubber (India), no other interested party has made any submission in this investigation. However, none of interested parties has provided any information with regard to the export price of the product under consideration from the subject countries to India. The Authority, on the basis of import statistics provided by DGCI&S, has determined the import volumes and export price of the subject goods from the subject countries.
31. The Price adjustments claimed by the domestic industry with regard to inland freight, handling, insurance, overseas freight and commission have been considered to arrive at ex-factory export price to India. The Authority has determined the ex-factory export price of subject goods for all exporters or producers from China PR and Thailand as follows:

		China PR	Thailand
Import volume	MT	28,653	32
Import value	Rs. Lacs	18,898.37	36.67
CIF import price	Rs./kg.	65.96	114.04
Exchange rate	Rs./US\$	41.08	41.08
CIF export price in US\$	US\$/kg	1.60	2.77
Price adjustments (total)	US\$/kg	0.10	0.13
Ex-factory export price	US\$/kg	1.50	2.64

### E 6. Dumping margin

#### E.6.1 Views of the Domestic industry:

32. The dumping margin is not only more than de-minimis, but also significantly high, causing material injury to the Indian industry.
33. Continued dumping and likelihood of continued dumping:

The present investigation is a mid-term review investigation and the Designated Authority is required to examine whether quantum of anti-dumping duty is required to be modified (enhanced). The Designated Authority is required to examine the need for continued imposition of anti-dumping duty and whether the quantum of anti dumping duty is required to be modified. Though the Designated Authority is not required to examine the likelihood or continuation of recurrence of dumping, nevertheless, the Applicant has provided information to show that dumping is likely to continue and cause injury to the domestic industry in case the present anti dumping duties are not enhanced appropriately. Followings are relevant in this regard-

- (a) Volume of exports have remained significant vis-a-vis original investigations as would be seen from the table below-

Year	Imports From Subject Countries (in numbers)	Increased as a % to the POI of Original investigation	Source
2001-02	3,589		As per Final findings of the original investigation
2002-03	16,735		
2003-04	77,538		
April 04-June,05 (POI)	2,16,851		
POI Annualized	1,73,481		
2005-06	3,24,997	87.33	DGCI&S Published data
2006-07	5,35,717	208.8	
2007-08	6,29,239	262.71	
Oct 07- Sept 08 (POI)	5,42,380	212.65	

It has been contended by the Applicant that the dumping margin determined in the original investigation and current investigation are significant.

- (b) Continued exports even after the imposition of duty at significantly dumping levels clearly show the need for enhancement in the benchmark.

#### **E.10.1 Views of the other interested parties:**

34. None of interested party has forwarded any information substantiating their claims in respect of dumping and continuation thereof.

#### **E.11. Examination By the Authority**

35. The Authority notes that the comparison of Normal value and Export price must be a fair comparison at the same level of trade; therefore the Authority has determined both the Normal value and Export price at ex-factory level. It is noted that the product is imported as set of tyre, tube & flap (TTF), or as a set of tyre & tube (TT), or only as tyre/tube or a flap. For the reasons already recorded above, the Authority has determined weighted average Normal value and weighted average Export price in respect of the product under consideration, by converting all imports on weight basis. There are no known differences in the conditions and terms of sale. No response has been filed by any exporter/producer from the subject countries in the instant matter. None of the interested parties have pointed out any possible factor, which could affect the comparability. Thus, the Authority considers that the comparison made constitutes a fair comparison. Considering the Normal value and Export price determined as detailed above, dumping margin has been determined, which comes as under:-

Particulars	Units	China PR	Thailand
Normal Value	US\$/KG	3.25	3.29
Export Price	US\$/KG	1.50	2.64
Dumping Margin	US\$/KG	1.75	0.65
Dumping Margin	%	116.67	24.62

The Authority notes that the dumping margins in respect of both the countries are above the de-minimis thresholds.

### **F. INJURY AND CAUSAL LINK DETERMINATION**

#### **F.1 Submissions of the domestic industry**

36. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link, in brief, are as follows:

- Product under consideration continues to be exported to India from the subject countries at dumped prices;
- Dumping has continued inspite of existing anti-dumping duties;
- Domestic industry has suffered continued injury;
- Domestic industry has not been able to improve its performance to the extent it could have;
- The current level of anti-dumping duties are grossly inadequate to prevent injurious dumping;
- Quantum of anti-dumping duties is required to be enhanced, considering the dumping margin and injury margin in the present investigation.

**F.2 Submissions of other interested parties**

37. The submissions have been filed by All India Tyre Dealers Federation and Asian Rubber (India). No other interested party has filed any submissions. There is no response from any producer/exporter from subject countries. Nor has any arguments been advanced on any aspect of the present investigations, including on injury & causal link from any exporters.

**M/s Asian Rubber (India)** has, *inter alia*, contended that:

- the petition filed by the domestic industry is incomplete and is half-baked.
- the selection of the present POI is the deliberate attempt of the domestic industry to seek the higher anti dumping duties on the basis of higher raw-material prices in the past, which no longer exists.
- the petitioner has failed to furnish information regarding injury or to establish that the benchmark prices are not sufficient to protect the industry from the dumping.
- despite requests, domestic industry did not provide the non-confidential version of the correspondences between the Designated Authority apart from other submissions. The company sought directions to the domestic industry to file the information relating to its performance from original investigation till current period of investigation in prescribed format.
- domestic industry has tried to hand pick and choose its opponents or respondent parties as against the known principles of jurisprudence. Any person getting affected by any such proposed action has a right to participate and furnish his views and contradict the claims of the domestic industry. This is the reason as to why the importers and other trade bodies could not make their representations earlier.
- the methodology of the petitioner to project increase in the raw material prices including that of rubber, crude oil prices for the determination of normal value is erroneous as the same is compared with the level of prices existing during the period 2001-02 whereas the definitive duty came into effect in the year 2007. The raw material price statement for the year 2007-08 shows prices at the high level which have now plunged significantly to a much lower level.
- reduction of excise duty by 4% across the board has improved the profitability of the domestic industry. Apart from this the reduction in raw material prices has also reduced the cost of production of the domestic industry.
- domestic industry has even failed to establish that the performance of the domestic industry has been impacted by such changed circumstances to warrant the enhancement of benchmark duty.
- the existing duty in dollar terms has provided more than adequate protection to the domestic industry than actually required. Due to fluctuation in US \$ and depreciation of Rupee by over 25-30 % which continues to remain depressed vis-a-vis US \$, domestic industry is over protected.

- The tyres imported from China PR are not comparable to one manufactured and sold by the domestic industry in terms of formulation as well as physical characteristics. The tyres imported from China PR are of lower quality with lesser size in dimension as compared to highly engineered tyres beefed with extra rubber and designed to carry much higher load.
- apart from the non-confidential version of the petition, no other document has been provided to the importers barring them to make effective representations. The questionnaire response filed by domestic industry, the injury information, dumping margin, export price, normal value on per set basis should be made available to the importer.
- the authority in its findings considered it appropriate to include size of tyres also within the scope of the investigation. It is requested that the scope of the product should be restricted to the scope of product as determined under the original investigations including size of tyres.
- evaluation and examination of economic parameters of the domestic industry should be done on the per set basis. The Authority should maintain consistency in adopting methodology for considering the net sales realizations, production, capacity and capacity utilization of the domestic industry.
- in the original investigation the opposing parties have raised the issue that some Indian manufacturers participating in the investigation are related to Chinese Exporters. Proof was also submitted with the Authority. Companies have entered in strategic tie-up with Chinese producers/exporters for the purpose of getting tyre manufactured under their own brand with strict quality control and supervision of Indian technical expert based in China. Not only Apollo, but other Indian producers such as CEAT and J.K Industries have also entered into such ventures in order to reap rich benefits of cost effective Chinese production technology.
- an appeal has been filed by the opposing interested parties including exporter, which is pending in CESTAT. The standing of the domestic industry should be determined only after the consideration of its relation with the Chinese exporters/exporters.
- the rubber and raw material used for the production comes in various grades and their costs differs significantly on grade to grade basis. The use of particular grade of raw material decides the ultimate price of the tyre. Domestic industry is producing super specialty tyres while those exported from the subject countries are of poor quality and are designed where performance is not a critical factor. Thus there is cost undercutting which most of Indian producers do not bother to look into. This is the reason for higher domestic prices and lower prices of Chinese tyres.
- it is claimed by the domestic industry that the imports have increased after imposition for which contrary figures are provided by the domestic industry.
- it is submitted that the imposition of antidumping duty does not mean banning of imports but to make the importation of the same at the fair price. Therefore, to argue that the imports are taking place from subject countries despite imposition of anti dumping duty lacks any merit and should be dismissed.

- contrary to the allegation of the domestic industry, the imports from subject countries declined significantly during period of investigation and import price has also increased, which shows that duty at its present form and level is more adequate to ensure the imports at un-dumped prices.
- with the decrease in raw material prices and due to depreciation in Rupee value by 25% the existing benchmark duty is more on a higher side. Further, the price hike by the petitioner even when there was no duty in place clearly suggests that the price rise by the petitioners have not been hindered by the importation of the subject goods
- the Annual reports of various companies comprising domestic industry shows profit in the subject product market.
- both the cost of production and sales realization increased during POI. The decline in profits cannot be attributed to the imports of subject goods as the difference between the same and yet domestic industry continued to hold significant market share even after increasing its prices.
- the demand of the product under consideration has increased. Capacity, production, sales and market share of the domestic industry have increased with decline in capacity utilization. Also, employment, wages and productivity have increased. The inventories have grown but it cannot be treated as injury since it includes export sales also. This does not show any injury to domestic industry due to imports from the subject countries.
- both price undercutting and price underselling are identical and in the range of 40-50% making it evident that sales realization and non-injurious price of the domestic industry are same. This shows that domestic industry is selling at non-injurious price and not suffering any injury.
- there is no increase in imports from China PR. Domestic industry has sufficiently maintained the market share with increase in sales and production. Even consumers did not switch over to Chinese imports making it evident that there is no causal link from the imports from China PR and injury.

**All India Tyre Dealers' Federation** in its submissions has, *inter alia*, stated the following:

- Since imposition of anti-dumping duty and fixation of reference price from September / October 2007 on the import of these tyres there has been several price hikes by the domestic tyre majors as there has been increase in raw material prices (both Natural Rubber and petro product based inputs). But later when the raw material prices crashed to last five year low, the tyre prices have not been accordingly rolled back by the oligopoly of domestic tyre makers.
- In the meanwhile, the Indian Rupee has depreciated in comparison to US dollar, thereby leading to imports becoming costlier by 25% - 30% in last two years. Thus, under these circumstances domestic industry should not be allowed to have the protection from import of these nylon fabric truck/bus tyres by way of continuing with anti-dumping duty.
- It is high time that designated authority should withdraw ongoing anti-dumping duty on import of tyres from China and Thailand and help the domestic road transport industry and tyre trade to benefit from free play of



market forces. This will further put some restraint on indiscriminate pricing policies of domestic tyre cartel and help the customers and reduce the transportation cost for essential commodities.

### **F.3. Examination by the Authority**

- With regard to alleged deficiencies/incompleteness in the application, the Authority observes that investigations are required to be initiated in case the application shows sufficient evidence of changed circumstances necessitating a review. The Authority does not require complete information as is necessary for final determination at the stage of initiation.
- With regard to selection of the POI, the Authority notes that changes in prices of raw materials justify the review of anti-dumping duties in case the anti-dumping duties are in the form as recommended in the present case. At the time of original investigations, the domestic industry had pleaded upwards revision in the benchmark on the grounds of increase in the input prices after the period of investigation taken by the Authority. However, the Authority consistently considers the prices of the major raw materials as prevailing during the period of investigation.
- As regards the sufficiency of the benchmark duty, the investigation establishes that the dumping margin, price undercutting and injury margin are at significant level.
- As regards the communications received from the domestic industry and various parties before initiating the investigations, the application filed by the domestic industry which formed the basis of initiation and all subsequent submissions made by the interested parties have been disclosed to interested parties through public file maintained in terms of Rule 6(7) of the AD Rules.
- As regards the participation by the parties, the Authority notes that the interested parties participate in the investigations before the Designated Authority. The domestic industry cannot decide who should be the interested parties and who should respond. Interested parties have been defined under the Rules and Authority has provided all reasonable opportunities to all the interested parties. It is, however, noted that none of the importers or consumers or foreign producers have filed questionnaire response. M/s Asian Rubbers also has not filed the questionnaire response. The Authority has, however, taken note of submissions made by interested parties.
- As regards incorrect claim of increase in raw material prices by the domestic industry, the Authority notes that it has re-determined all parameters in the present investigations. Further, the Applicant has provided information over the injury period and for the POI in order to justify its claim of changed circumstances. However, the same does not imply that the price increase has been considered between the current POI and that of the base year of the original investigation.
- As regards improvement in profitability due to reduction in Excise Duty, the Authority notes that actual profitability of the domestic industry in the period under reference has been considered which includes alleged impact of Excise Duty as well. If the argument of the interested parties were to be accepted, it implies that the profitability of the domestic industry would have been more

adverse than what has been found in the present investigation, were the excise duty not been reduced by the Govt. of India.

- The Authority notes that even the prescribed proforma for Mid-term review available on the Website of DGAD clearly lists some of the factors which constitutes changed circumstances and includes changes in non-injurious price, normal value, landed price of imports, etc., necessitating a review. The Authority considers that changes in any of these parameters alone could be sufficient in establishing the need for a review. In the instant matter, the Applicant has provided sufficient information to establish the need for the review.
- As regards changes in Exchange Rate, the Authority notes that actual Exchange Rate prevailing in the POI has been considered in the present investigations.
- As regards alleged claim of incomparability of the imported tyre and tyres supplied by the domestic industry, the Authority notes that the argument has not been substantiated. The Authority has made available all relevant evidence through public file.
- So far as this mid-term review investigation is concerned, the Authority notes that it is required to undertake examination of various parameters during the period of investigation. In any case, it has not been established by the interested parties opposing the Applicant's claims that current situation does not justify either change in the quantum or extension of anti-dumping duties.
- As regards the scope of PUC of this investigation, the Authority is of the view that since the product under consideration in the previous investigation that is being reviewed was "new/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" originating in or exported from China PR and Thailand; the scope of this investigation remains the same.
- As regards relationship of Indian producers with the Chinese producers or the imports by the Indian producers, the Authority notes that the Applicant has clarified the matter and as per the letters filed by the Applicant, M/s Apollo Tyres Ltd., M/s Ceat Ltd., M/s Birla Tyres (A unit of Kesoram Industries Ltd.), M/s MRF Ltd., M/s JK Tyre & Industries Ltd. have, *inter alia*, stated that they are not related to either to a producer-exporter of the product in China PR and Thailand or an importer in India.
- As regards the claim of the domestic industry that imports have increased after imposition of duty, the Authority notes that the domestic industry in their written submissions claimed that the import price got so re-aligned that the quantum of anti-dumping duties paid gradually declined to nil. The domestic industry claimed that after re-aligning the import price, significant imports of the product have continued to be made in the Country. Further, the domestic industry has contended that the imports of the product were at continued dumped prices; thereby undercutting the prices of the domestic industry. Besides these were as well at prices much below the non injurious price of the domestic industry.
- Regarding current imports, the Authority agrees with the interested parties that the purpose of imposition of anti-dumping duties is not to prohibit imports. However, the argument of the domestic industry is that imports reported are at

dumped prices and are significantly undercutting the domestic prices. Besides, and also the injury margin is also significant.

- As regards the domestic industry data does not shown losses, the Authority notes that the claim of the domestic industry in this mid-term investigation is that the current duty is not sufficient to address the injury earlier established. The domestic industry has asked for modification in the form and enhancement in the quantum of duty.
- Regarding the Annual reports showing profits, the Authority notes that the information does not show financial losses. However, existence of financial losses is not a pre-requisite for modification of duties. In fact, while undertaking the injury analysis it is to be appreciated that the list of factors enumerated under the law are neither exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance. Further, the domestic industry has filed the present application for change in the form and enhancement in the quantum of anti dumping duties on the grounds that the situation was leading to continued dumping and was not adequately addressing injury caused thereof to the domestic industry.
- As regards the costs & prices, it is noted that both cost of production and sales realization have increased; however, while the increase in the cost of production was less than the increase in the sales realization till 2007-08, the increase in the sales realization in the POI was less than increase in the cost of production.
- The Authority has examined the injury parameters and the determination is based on the performance of the domestic industry. Given that the present investigation is in the nature of a mid-term review investigation, improvements in one or more parameters since imposition of anti dumping duties could be a result of the imposition of anti dumping duties. However, the present application is for change in the form and increase in the quantum of duty on the grounds that the present duty is insufficient and is leading to continued dumping of the product.
- The Authority further notes that increase in the volume of imports is not a pre-requisite in a mid-term review. Continued imports of the product after imposition of anti dumping duties at dumped prices, which undercuts the prices of the domestic industry after addition of anti dumping duties and positive injury margin etc are sufficient to take a view that present duties are required to be modified.
- The Authority also notes that though M/s Asia Rubber (India) stated that they are providing the dimensional comparison between the Chinese and Indian tyres but the same was not received.
- The Authority has taken note of the contention that the Indian Rupee has depreciated in comparison to US dollar, thereby leading to imports becoming costlier by 25% - 30% in last two years. The Authority reiterates that so far as this mid-term review investigation is concerned, it would duly consider all factors prevalent during the period of investigation.

38. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to

the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

39. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

*"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."*

40. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.
41. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any. Accordingly the volume and price effects of dumped imports have been examined as follows.

**A. Volume Effect**

**a) Assessment of Demand**

42. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India, which has been summarized as under:

In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Imports from Subject countries	MT	18,224	29,481	36,419	28,685
Imports from other countries	MT	5,977	2,814	1,110	422
Total imports	MT	24,201	32,295	37,529	29,107
Sale of domestic industry	MT	387,561	419,173	434,772	460,038

Sales of other Indian Industry	MT	128,262	134,222	142,252	135,121
Demand	MT	540,024	585,690	614,553	624,266

In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Imports from Subject countries	Nos	306,122	452,028	471,394	504,169
Imports from other countries	Nos	113,738	48,476	20,632	6,607
Total imports	Nos	419,860	500,504	492,026	510,776
Sale of domestic industry	Nos	6,743,169	7,249,446	7,710,366	8,188,490
Sales of other Indian Industry	Nos	2,420,029	2,532,485	2,683,995	2,549,444
Demand	Nos	9,583,058	10,282,435	10,886,387	11,248,710

The Authority notes that the demand has shown a positive trend and grew over the injury period both in terms of weight and numbers/pieces. The growth in demand during period of investigation over base year was about 15.60 % in terms of weight and in terms of numbers/pieces about 17.38%.

b) Import volumes and market share

43. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that "while examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India .....". Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

The volumes of imports from the two countries were as follows:

In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
➤ China PR	MT	17,455	29,265	36,406	28,653
➤ Thailand	MT	769	216	13	32

Imports from Subject countries	MT	18,224	29,481	36,419	28,685
Imports from other countries	MT	5,977	2,814	1,110	422
Total imports	MT	24,201	32,295	37,529	29,107
Share of Imports					
➤ China PR	%	72.12	90.62	97.01	98.44
➤ Thailand	%	3.18	0.67	0.03	0.11
Imports from Subject countries	%	75.30	91.29	97.04	98.55
Imports from other countries	%	24.70	8.71	2.96	1.45
Imports in relation to Production in India					
➤ China PR	%	2.84	4.64	5.42	4.26
➤ Thailand	%	0.125	0.034	0.002	0.005
Consumption in India					
➤ China PR	%	3.23	5.00	5.92	4.59
➤ Thailand	%	0.142	0.037	0.002	0.005

In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
➤ China PR	Nos	292,922	448,113	471,331	503,723
➤ Thailand	Nos	13,200	3,915	63	446
Imports from Subject countries	Nos	306,122	452,028	471,394	504,169
Imports from other countries	Nos	113,738	48,476	20,632	6,607
Total imports	Nos	419,860	500,504	492,026	510,776
Share of Imports					
➤ China PR	%	69.77%	89.53%	95.79%	98.62%
➤ Thailand	%	3.14%	0.78%	0.01%	0.09%

Imports from Subject countries	%	72.91%	90.31%	95.81%	98.71%
Imports from other countries	%	27.09%	9.69%	4.19%	1.29%
Imports in relation to Production in India					
➤ China PR	%	2.53%	3.77%	3.72%	3.97%
➤ Thailand	%	0.114%	0.033%	0.000%	0.004%
Consumption in India					
➤ China PR	%	3.06%	4.36%	4.33%	4.48%
➤ Thailand	%	0.138%	0.038%	0.001%	0.004%

From the above, the Authority notes that:

- Chinese imports of the product have increased significantly as compared to the base year, though in terms of weight there has been a dip in imports during the POI as compared to 2007-08 period.
- Imports from Thailand have declined significantly as compared to the base year both in terms of weight and numbers/pieces. Even though the volumes increased in POI as compared to 2007-08 period, the same is still quite low.
- Even when the subject imports are attracting anti dumping duties, the imports from China PR have increased in relation to production and consumption in India when compared with the base year both in terms of weight and numbers/pieces.

## **B. Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry**

- In order to ascertain the price effect of the imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry, the Authority has examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry, even after considering the anti-dumping measure in force. Landed price from subject countries including applicable customs duty is significantly below the net sales realization and non-injurious price of the domestic industry. Apparently, the Chinese exporters have continued to export the subject goods at dumped prices, which is reflected in the price undercutting and price underselling, particularly in the context that the anti dumping measures are already in force.

In terms of weight

Particulars	Unit	China PR	Thailand	Subject Countries
-------------	------	----------	----------	-------------------

CIF Price	Rs/KG	65.96	114.04	66.01
Landing Charges	Rs/KG	0.66	1.14	0.67
Assessable Value	Rs/KG	66.62	115.18	66.68
Custom Duty	%	10.00	10.00	10.00
Basic Customs Duty	Rs/KG	6.66	11.52	6.67
Cess on Custom Duty	Rs/KG	0.20	0.35	0.20
Cess on CVD	Rs/KG	0.33	0.57	0.33
Landed Price	Rs/KG	73.15	126.47	73.21
ADD Benchmark	Rs/KG	100.91	100.91	100.91
ADD Payable	Rs/KG	27.76	-	27.70
Landed Price with ADD	Rs/KG	100.91	126.47	100.91
Net sales realization	Rs/KG	****	****	****
Price Undercutting	Rs/KG	****	****	****
Price Undercutting	%	85-90	5-10	85-90
Price Undercutting with ADD	Rs/KG	****	****	****
Price Undercutting with ADD	%	32-37	5-10	32-37

### **Price suppression/depression**

45. In order to assess whether the imports from the subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry, the Authority has made comparison of cost of production and selling price of the domestic industry along with the landed price of imports, which is given in the following table:

In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI (Oct'07-Sep'08)
Cost of Production	Rs./kg	100.00	111.30	115.81	128.63
Selling Price	Rs./kg	100.00	111.96	119.65	125.60
Landed price of imports	Rs./kg	46.26	68.66	65.51	73.21



<input type="checkbox"/> China PR	Rs./kg	46.25	68.73	65.44	73.15
<input type="checkbox"/> Thailand	Rs./kg	46.53	59.33	282.06	126.47
Changes in					
Cost of Production	Rs./kg		11.30	4.50	12.83
Selling price	Rs./kg		11.96	7.69	5.95
Landed price of imports	Rs./kg		22.40	(3.15)	7.69
<input type="checkbox"/> China PR	Rs./kg		22.48	(3.29)	7.71
<input type="checkbox"/> Thailand	Rs./kg		12.80	222.74	(155.60)

### Economic Parameters relating to the Domestic Industry

46. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

### Production, sales, capacity and capacity utilization

47. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below.

In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Capacity	MT	443,613	477,177	501,548	506,341
Production	MT	447,512	468,842	487,353	482,887
Capacity Utilization	%	100.88	98.25	97.17	95.37
Sales	MT	387,561	419,173	434,772	460,038
Demand	MT	540,024	585,690	614,553	624,266

In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Capacity	Nos	8,612,867	9,147,251	9,894,774	10,020,180
Production	Nos	8,688,566	8,987,470	9,598,703	9,556,049
Capacity Utilization	%	100.88	98.25	97.01	95.37
Sales	Nos	6,743,169	7,249,446	7,710,366	8,188,490
Demand	Nos	9,583,058	10,282,435	10,886,387	11,248,710

It is noted that:

- a) The domestic industry has added capacity over the injury period. It is noted that with the increase in demand by about 15.60% (in terms of weight), the domestic industry has added additional capacity by about 14.14%. In terms of numbers, the demand increased by about 17.38% as compared to the addition in capacity of about 16.34%.
- b) Production of the domestic industry increased till 2007-08 as compared to the base year both in terms of weight and numbers/pieces. However, whereas the demand increased by about 15.60% (in terms of weight) and by about 17.38% (in terms of numbers/pieces); the production increased only by 7.90% (in terms of weight) and 9.98 % (in terms of numbers/pieces). It is thus noted that the domestic industry has not been able to improve its production to the extent of enhanced capacity or the increase in demand.
- c) Sales of the domestic industry increased both in terms of weight and numbers/pieces. Thus, the domestic industry has been able to improve its sales volumes after imposition of anti dumping duties. The domestic industry has, *inter alia*, contended that the sales could have increased further, but for continued dumping and that increase in imports prevented growth in production, capacity utilisation and sales volumes.

Profit, Return on Capital employed and Cash flow

48. Profits, Return on Capital employed and Cash flow moved as shown below:

In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Profit/Loss before tax	Rs./Kg	100.00	125.19	197.01	64.55

Profit/loss before interest	Rs./Kg	100.00	119.82	170.89	79.92
Return on Investment	%	100.00	120.46	163.21	73.67
Cash Profit	Rs./Kg	100.00	120.72	179.86	86.91

In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Profit/Loss before tax	Rs./Set	100.00	126.95	195.68	60.86
Profit/loss before interest	Rs./Set	100.00	118.18	173.90	80.54
Return on Investment	%	100.00	120.46	163.21	73.67
Cash Profit	Rs./Set	100.00	119.14	183.18	87.57

49. The Authority notes that the profitability of the domestic industry improved till 2007-08 after imposition of anti dumping duties both in terms of weight and numbers/pieces. However, profitability declined sharply in the POI even below the levels registered in the base year. Further, both profit before tax and profit before interest shows the same trend. Return on Capital employed and Cash profit show the same trend as that of profits. Return on capital employed and Cash profit improved till 2007-08, but declined sharply in the POI. All the domestic producers are multi-product companies and cash flow situation of the company would not be indicative of the situations in the subject product. Hence the Authority has examined cash profits over the years and the same is shown as above.
50. The Authority examined profitability by considering the trends in the cost of production and selling prices over the injury period. It is found that both the cost of production and the selling prices increased throughout the injury period. However, whereas the increase in the selling prices was more than the increase in the cost of production till 2007-08, the increase in the cost of production was far higher than the increase in the selling prices during the POI. Consequently, profitability of the domestic industry suffered during the POI.

In terms of weight (indexed)

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Cost of Production	Rs./kg	100.00	111.30	115.81	128.63
Selling price	Rs./kg	100.00	111.96	119.65	125.60
Profit/loss	Rs./kg	100.00	125.19	197.01	64.55
Increase in					
Cost of production	Rs./kg		100.00	39.85	113.56
Selling price	Rs./kg		100.00	64.35	49.78

In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Cost of Production	Rs./Set	100.00	111.59	113.52	126.77
Selling price	Rs./Set	100.00	112.31	117.40	123.66
Profit/loss	Rs./Set	100.00	126.95	195.68	60.86
Increase in					
Cost of production	Rs./Set		100.00	16.70	114.30
Selling price	Rs./Set		100.00	41.32	50.82

Market share

51. Comparison of the sales of the domestic producers and imports from subject countries shows that although the market share of the participating domestic industry has marginally increased, the market share of Indian Industry as a whole declined marginally with the increase in the share of subject imports from subject countries during the POI as compared to the base year.

In terms of weight

Market share	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Domestic Industry	%	71.77	71.57	70.75	73.69
Other Indian producers	%	23.75	22.92	23.15	21.64
Total Indian Industry	%	95.52	94.49	93.89	95.34
Imports from subject countries	%	3.37	5.03	5.93	4.60
Imports from other countries	%	1.11	0.48	0.18	0.07

In terms of numbers/pieces

Market share	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Domestic Industry	%	70.37	70.50	70.83	72.79
Other Indian Industry	%	25.25	24.63	24.65	22.66
Total Indian Industry	%	95.62	95.13	95.48	95.46

Imports from subject countries	%	3.19	4.40	4.33	4.48
Imports from other countries	%	1.19	0.47	0.19	0.06

### Employment, wages and productivity

Position with regard to employment, wages & productivity shows as follows

#### In terms of weight

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
No. of employees	Nos.	100	104	112	112
Wages	Rs.Lac	100	111	121	131
Wages Per Unit	Rs./KG	100	105	111	121
Productivity per Employee	MT	100	100	95	95

#### In terms of numbers/pieces

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
No. of employees	Nos.	100	104	112	112
Wages	Rs.Lac	100	111	121	131
Wages Per Unit	Rs./Set	100	105	194	156
Productivity per Employee	Nos	100	99	97	92

52. However, the Authority notes that all the domestic producers are multi-product companies and hence the employment by the domestic industry and wages paid may not be a correct parameter to evaluate injury in the instant matter.

### Inventories

53. Inventories of the domestic industry have shown a rising trend.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Average Inventories	MT	100	122	140	189
Stock as a no. of days sales	Days	100	108	125	158

The Authority notes that though the inventories of the domestic industry were expected to decline with the imposition of anti dumping duties but the inventories have

increased. This apparently shows that domestic industry has not been able to sell the increased production in the market.

### Growth

54. The Authority notes that the growth of the domestic industry was positive till 2007-08. However, growth became negative in the POI in terms of profits, cash profits, return on investment and inventories show adverse trend during the POI, even though this was positive in respect of production and sales volumes.

55. Likelihood of continued dumping & injury

- a. The Authority notes that at the current level of benchmark, the landed price of imports is below the net selling price and non-injurious price of the domestic industry.
- b. Imports of the product from China PR have increased significantly over the injury period. Even though there was some decline in the import volumes during the POI, still the volume of imports in the POI were at higher levels as compared to the base year. The imports have dipped as compared to 2007-08 period, but this could also be on account of the anti-dumping measure in force.
- c. Although the production, capacity and sales of the domestic industry have increased over the injury period; the capacity utilization, profitability, return on investment and cash profits have declined during the POI vis-à-vis the base year. The imports at dumped prices are resulting in price undercutting, price suppression and there is a case of price underselling as well. The situation of domestic industry continues to be vulnerable and dumped imports from the subject countries continue to cause material injury to the domestic industry.

### Conclusions on injury

56. Thus, the Authority notes that the various parameters relating to domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury. While volume parameters like capacity, production and sales have increased in absolute terms, but the same have not increased corresponding to the increase in consumption of the subject goods in India. Further, profitability of the domestic industry has deteriorated in the POI, apparently because of the continued dumped imports.

### Causal Link

57. Views of the Domestic Industry

- a. Material injury has been caused to domestic industry from dumped imports from China and Thailand. Imports from other countries are de-minimis. The petitioner companies are producing the subject goods for the past several years. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology adopted by other players in the world-market. There is no significant difference in the manufacturing process. In fact technology for production is fairly matured,

established and standardized, with little technological innovations and developments. There are no other factors for this injury but for the dumping.

- b. Landed price of imports from the subject countries were significantly below the selling price and cost of production of domestic industry causing significant price undercutting. The increase in imports is because of positive price undercutting in spite of existence of anti dumping duties;
- c. As a result of positive price undercutting, the domestic industry has been prevented from increasing its prices to the extent of non-injurious price. Continued dumped imports are therefore resulting in continued price undercutting,
- d. Volume of imports increased in terms of numbers because of positive price undercutting. Consequently market share of imports remained significant (in fact increased) in spite of existing anti dumping duties and that of Indian producers declined. Increase in volume of imports as a result of significant price difference prevented the domestic industry from increasing its production and sales to the extent of imports.
- e. Duty paid import price from subject countries vis-à-vis prices of the domestic industry shows that the imports are undercutting the prices of the domestic industry even after addition of current level of anti dumping duties.
- f. Price suppression & depression effect which the subject imports have had on the domestic industry has lead to decline in profitability over the injury period and consequent deterioration in return on investment and cash flow.
- g. In a situation where the exporters continue to export significant volumes to India in spite of existence of anti dumping duties, it follows that the volumes would at best increase with the revocation of anti dumping duties.
- h. The landed value from the subject countries has been below the net sales realization of the domestic industry. In fact, the price undercutting would at best intensify in the event of revocation of anti dumping duties. Thus, possible revocation would thus result in significant price undercutting and underselling.
- i. The imports continued to cause price undercutting. Resultantly, the volume and market share of imports increased. As a direct consequence, market share of the domestic industry declined.
- j. Increase in imports and market share and consequent prices offered by the domestic industry directly resulted in further deterioration of profit/loss situation, ROI and cash flow suggests that the situation of the domestic industry would remain adverse in the situation of continued subject imports.

#### **Examination by the Authority**

58. The Authority has examined whether other parameters could have contributed to injury to the domestic industry. Following parameters were analyzed.

- a) Imports from Third Countries: - Imports of subject goods from other countries are negligible or below the de-minimis thresholds. Thus, the imports from other countries do not appear to have caused injury to the domestic industry.
- b) Contraction in Demand:- It is noted that the demand for the subject goods has increased; thus possible contraction in demand cannot be the cause of injury to the domestic industry.
- c) Pattern of consumption:- No significant change in the pattern of consumption has been noticed. The product supplied by the domestic industry is directly competing with that of imported material from the subject countries. The demand for the subject goods has shown an increase and it does not appear that the pattern of consumption has caused injury to the domestic industry.
- d) Conditions of competition:- As per facts available on record, there is no evidence that conditions of competition or trade restrictive practices have caused injury to the domestic industry.
- e) Developments in technology:- As per facts available on record, there appears to be no change in technology over the injury period which could have caused injury to the domestic industry.
- f) Export performance of the domestic industry: - The performance of the domestic industry has been segregated for domestic sales and exports sales; and only domestic performance of the domestic producers have been considered while assessing the injury to the domestic industry.
- g) Productivity: - It is noted that the productivity of the domestic industry has declined.

59. Thus, the Authority holds that the performance of the domestic industry over the injury period has deteriorated due to dumped imports from subject countries. This is apparently established by the following:

- i. Landed price of imports from the subject countries are significantly below the net selling price and the non-injurious price of the domestic industry, thereby causing significant price undercutting and price underselling. As a direct consequence thereof, the domestic industry was not able to achieve a higher sales realization to the extent of the increase in costs.
- ii. The above situation has also caused price suppression, resulting in deterioration in profits and return on investments.
- iii. Price undercutting and price suppression being caused by the dumped imports is preventing the domestic industry from realizing non injurious price.

60. Thus, the Authority concludes that the dumped imports originating in or exported from the subject countries have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 read along with Annexure II of the AD Rules.



**D. Likelihood of recurrence of dumping and injury**

61. The Authority notes that dumping is continuing from China PR and Thailand in spite of the antidumping duty in force and the domestic industry continues to suffer material injury due to such dumped imports. Therefore, further examination of the likelihood of recurrence of dumping and injury is not required.

**H. CONCLUSIONS**

62. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from subject countries is significant and above de-minimis limits prescribed. The subject goods continue to be exported to India at dumped prices inspite of existing anti dumping duties.
- ii. Considering the facts available on record, the subject goods are likely to enter Indian market at dumped prices, should the present measures be withdrawn.
- iii. The situation of domestic industry deteriorated further in spite of existing anti dumping duties. Further, should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify.
- iv. The deterioration in the performance of the domestic industry is because of dumped imports from the subject countries.
- v. The current level of anti dumping duty is insufficient to address continued dumping and consequent injury to the domestic industry and thus the anti-dumping duty is required to be modified.

**I. RECOMMENDATIONS**

63. Having concluded that the product continues to be exported at dumped prices, the current dumping margin and injury margin establishes the need for revision in the anti-dumping duty in force, the situation of the domestic industry continues to be vulnerable and there is likelihood of continuation of dumping and injury on account of imports from subject countries, if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended and the quantum of Anti-dumping duty is required to be modified in respect of imports from subject countries as specified in the duty table below. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation.
64. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the difference between the amount indicated in Col 8 of

the table below and the landed value is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

**Duty Table**

Sl. No	Heading / Subheadings	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16	Thailand	Thailand	Any	Any	0.37	Kg	US \$
2.	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16	Thailand	Any country other than Thailand	Any	Any	0.37	Kg	US \$
3	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	0.37	Kg	US \$
4.	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with	China PR	China PR	Any	Any	1.64	Kg	US \$

		or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16							
5.	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.64	Kg	US \$
6.	40112090 , 40131020 and 40129049	New/unused pneumatic non radial bias tyres, tubes & flaps with or without tubes and/or flap of rubber, having nominal rim dia code above 16	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	China PR	Any	Any	1.64	Kg	US \$

65. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

66. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

P. K. CHAUDHERY. Designated Authority